राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 11 जनवरी 2026 वर्ष-8,अंक-315 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 लोगों की मौत का दावा

■ सेना बोली: बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें

एजेंसी

तेहरान। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई हैं। सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात प्रदर्शन तेज होने पर कई जगहों पर गोलीबारी की थी, इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी से बात करते चेतावनी दी कि माता-पिता अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, अगर उन्हें गोली लगे तो शिकायत मत करना। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले कुछ दिनों तक यह साफ नहीं था कि सरकार क्या रुख अपनाएगी। खुद एंटी राइट्स पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बल भ्रम में हैं। किसी को ठीक से नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन शुक्रवार को सामने आई खूनी तस्वीरों और सख्त बयानों से साफ हो गया कि अब पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने देशभर में इंटरनेट और फोन सर्विस लगभग बंद कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ईरानी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

मेरठ: कपसाड़ में मीडिया कवरेज पर रोक

■ पत्रकार से पुलिस की धक्का-मुक्की

एजेंसी

मेरठ। सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में कवरेज के लिए पहुंचे एक निजी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संवाददाता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने का आरोप सामने आया है। मीडियाकर्मियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जबरन कवरेज से रोकने का प्रयास किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बताया गया कि कपसाड़ गांव के सभी मुख्य रास्तों और संपर्क मार्गों पर पुलिस की कड़ी घेराबंदी है। मीडिया कर्मियों के गांव में प्रवेश पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ मीडियाकर्मी पगडंडियों के रास्ते गांव में पहुंचने में सफल रहे। पीड़ित मीडियाकर्मी के अनुसार, वह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे, जहां पूर्व विधायक संगीत सोम मौजूद थे और वह उनसे पूरे मामले पर बातचीत करना चाहते थे। इसी दौरान पीड़ित परिवार के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन रोक लिया। मीडियाकर्मी का आरोप है कि जब उन्होंने रोके जाने का विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की।

ओडिशा में 9 सीटर चार्टर फ्लाइट की क्रैश लैंडिंग

2 पायलट समेत 4 यात्री घायल, इनमें दो महिलाएं भी, विमान भुवनेश्वर से राउरकेला आ रहा था

एजेंसी

राउरकेला। ओडिशा के राउरकेला में शनिवार दोपहर 9 सीटर फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई। इंडिया वन एयर के चार्टर विमान की तकनीकी खराबी के बाद क्रैश लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 6 लोग सवार थे, जिनमें 4 यात्री और 2 पायलट शामिल हैं। सभी लोग घायल हैं। कुछ को गंभीर घाव हैं। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट भुवनेश्वर से राउरकेला आ रही थी। क्रैश की घटना राउरकेला से 10 Km दूर जाल्दा इलाके में हुई। क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नजर आ रहा है कि VT KSS प्लेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके विंग्स भी क्षतिग्रस्त हैं। ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी बी जेना ने कहा कि अ-1 कैटेगरी का प्राइवेट विमान क्रैश हुआ। इसमें पायलट समेत 6 लोग सवार थे। सभी को चोटें आई हैं, उनका इलाज जारी है। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना की जानकारी DGCA को दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट अक 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, जहां विमान गिरा था, वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे। एक व्यक्ति जीवित बचा था। फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, विमान का

आखिरी सिग्नल 190 मीटर (625 फीट) की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया था कि उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल (इमरजेंसी मैसेज) भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। DGCA के अनुसार, पायलट के पास 8,200 घंटे और को-पायलट के पास 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही स्थानीय लोगों ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। कुछ ही देर में पुलिस-प्रशासन ने भी पहुंच कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार यह एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली नियमित उड़ान थी। मंत्री जेना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यात्रियों को ले जा रहा एक अ-1 नौ सीटर प्राइवेट विमान हादसे का शिकार हो गया है। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। यह घटना राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जल्दा में हुई।

डोभाल बोले: जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं

हम मनोरोगी नहीं कि शव देखकर खुशी मिले, मौजूदा लीडरशिप ने 10 साल में देश बदला

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि युद्ध राष्ट्र की इच्छाशक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा, 'हम साइकोपैथ (मनोरोगी) नहीं हैं, जिन्हें दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयां इसके लिए नहीं लड़ी जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वह हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। अजीत डोभाल ने शनिवार को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बाते कहीं। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप अपनी इच्छाशक्ति बढ़ा सकते हैं। वही इच्छाशक्ति राष्ट्रीय शक्ति बन जाती है। दुनिया में हो रहे सभी युद्ध और संघर्षों को देखें तो साफ है कि

कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं। इसके लिए अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई देश इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका विरोध न कर सके तो वह हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अगर संसाधन और हथियार हों, पर मनोबल न हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मनोबल बनाए रखने के लिए लीडरशिप जरूरी होती है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है। एक ऐसा लीडर जिसने 10 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए। अपमान झेला और बेबसी के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी हुई। हमारे गांव जलाए गए। हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया गया। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए। 'बदला' शब्द शायद बहुत अच्छा न लगे, लेकिन बदला खुद एक ताकतवर एहसास है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। हमें इस देश को उस मुकाम पर वापस ले जाना है, जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वास के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हम कहीं लूटने नहीं गए। हमने किसी दूसरे देश या लोगों पर हमला नहीं किया, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और खुद को लेकर आने वाले खतरों को समझने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश और विदेश से आए 3,000 से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री भारत मंडपम में आयोजित डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। डायलॉग में चुने हुए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के सामने 10 अलग-अलग विषयों पर अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे।

ओवैसी बोले : भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी

■ भाजपा नेता का जवाब- हिंदू राष्ट्र में संभव नहीं

एजेंसी

मुम्बई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहीं हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा में ये बयान दिया। AIMIM प्रमुख ने कहा- पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ओवैसी के बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने दिया। उन्होंने मीडिया से कहा- ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। जो लोग ऐसे पदों पर बैठना चाहते हैं, उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। हम बुर्के वाली और हिजाब पहनने वाली के साथ

ओवैसी को भी बैठाएंगे और यहां से भगा देंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई अन्य पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका अंत होगा। जब प्यार आम हो जाएगा, तो लोगों को एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग में कैसे जहर घोला गया था। इस पर BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन ओवैसी को चुनौती देता हूं कि पहले आप किसी पसमांदा या हिजाब वाली को अक्टक्ट का अध्यक्ष बनाएं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि संविधान के अनुसार कोई रोक नहीं है।

अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश: मंदिर में घुसे लोगों ने खुद को कश्मीर का बताया

एजेंसी

अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर में शनिवार सुबह 3 लोग घुस गए और नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। पकड़े गए 2 युवक और 1 लड़की ने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया है। अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आरोपी कौन हैं और कहां के हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। युवक से पूछताछ की जा रही है कि वह अयोध्या क्यों आया? युवक और युवती राम मंदिर के गेट ऊा से घुसे। इसके बाद सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए

युवक बैठ गया। पुलिसवालों ने उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया। युवक कश्मीरी वेशभूषा में थे। पकड़े गए एक युवक का नाम अबू अहमद शेख है। वह कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। वहीं, पकड़ी गई लड़की नाम सोफिया है। दूसरे लड़के का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने जब युवकों को रोका, तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, इस मामले पर जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

चुनाव आते ही ईडी को याद आते हैं दस्तावेज': कपिल सिब्बल

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई को लेकर राज्य से लेकर देशभर की राजनीति में गर्माहट तेज है। इसी बीच इस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई का मामला उठाया।उन्होंने कहा कि पश्चिम

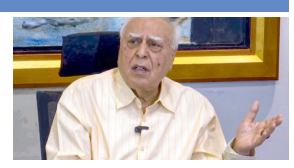

बंगाल में जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई भी जांच एजेंसी किसी दफ्तर में जाकर सभी फाइलें कैसे ले जा सकती है। अगर कोयला घोटाले की जांच करनी है तो उससे जुड़ी फाइलें लें, लेकिन हर फाइल ले जाना किस अधिकार में है?

जयपुर में अमित शाह ने 9000 कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए

बोले: इनको सिफारिश नहीं, योग्यता से नियुक्ति मिली

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने राम राम से भाषण की शुरूआत की। उन्होंने कहा-आज 9000 कॉन्स्टेबलों को किसी सिफारिश नहीं अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है जब नियुक्ति पारदर्शिता से की हो। भजनलाल ने कांग्रेस सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर उससे निजात दिलाई है। इससे पहले जोधपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा- माहेश्वरी समाज जॉब सीकर नहीं रहा, जॉब क्रिएटर रहा है। ऐसे ही सदियों तक यह समाज देश की सेवा करता रहे। राम मंदिर पर पुस्तक लिख रहा युवक मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या जानकारी है? उसने बताया कि आजादी के बाद राम मंदिर के लिए सबसे पहले प्राणों की आहूति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज से थे। अमित शाह ने कहा कि देश के सांस्कृति पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का योगदान बहुत बड़ा है। माहेश्वरी समाज के हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है, तराजू भी। समाज के दिए हुए भामाशाहों की सूची बनाएंगे तो कई पेज भर

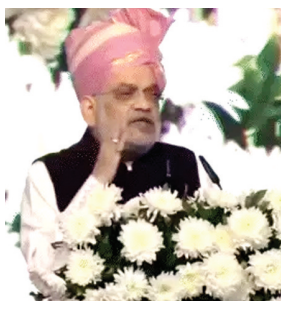

जाएंगे। शनिवार को शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में चल रहे माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- देश को हर क्षेत्र में सर्वप्रथम लाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, जिन्हें माहेश्वरी समाज कर सकता है। पहली, जो उत्पादन करते हैं तो वो करिए, लेकिन साथ में ऐसी चीजों का उत्पादन भी करें, जो भारत में नहीं बनती है। दूसरी, स्वदेशी। जितना हो सके, उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। यह तय कर लें कि मेरे देश में बनी है, उसी चीज का व्यापार करूंगा। स्वदेशी के साथ स्वभाषा का भी उपयोग करें। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तो राजा-महाराजा के खजाने भरने का काम माहेश्वरी समाज ने किया। जब अंग्रेजों से लड़े तो महात्मा गांधी की लड़ाई का खर्च माहेश्वरी समाज के सेठों ने उठाया है। जब देश आजाद हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।अमित शाह ने कहा कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, माहेश्वरी समाज ने प्रगतिशील समाज का परिचय दिया है। हमारे गुजरात में कहावत है कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। अमित शाह ने कहा कि जब समाज के आयोजन होते हैं तो कई प्रगतिशील लोग टीका-टिप्पणी करते हैं, मैंने ऐसी कई टिप्पणी झेली है। हमारे यहां समाजों के ऐसे महाकुंभ भारत को मजबूत करते हैं, भारत को विघटित नहीं करते। यदि हर समाज अपने गरीब भाई-बहनों की देखभाल स्वयं कर ले तो भारत से गरीबी मिट जाए। यदि हर समाज आत्मनिर्भर बन जाए तो पूरा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर पर पुस्तक लिख रहा युवक मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या जानकारी है? उसने बताया कि आजादी के बाद राम मंदिर के लिए सबसे पहले प्राणों की आहूति देने वाले दोनों भाई माहेश्वरी समाज से थे। अमित शाह ने कहा कि देश के सांस्कृति पुनर्जागरण में भी माहेश्वरी समाज का योगदान बहुत बड़ा है। माहेश्वरी समाज जॉब सीकर नहीं रहा, जॉब क्रिएटर रहा है। ऐसे ही सदियों तक यह समाज देश की सेवा करता रहे। जोधपुर में शाह ने कहा- माहेश्वरी समाज के हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है, तराजू भी।

ऊर्जा संस्थान में सीबीआई ने रिश्वत के खेल का किया भंडाफोड़

संयुक्त निदेशक 9.5 लाख लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए बंगलूरू स्थित केंद्रीय ऊर्जा शोध संस्थान के संयुक्त निदेशक राजाराम मोहन राव को 9.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक निजी कंपनी के अधिकारी को भी पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी से सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई के अनुसार, 8 जनवरी को संयुक्त निदेशक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोप था कि संयुक्त निदेशक निजी कंपनी सुधीर ग्रुप ऑफ कंपनीज के बनाए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पक्ष में जांच रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत मांग रहा था। पुख्ता सूचना के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और शुक्रवार को बंगलूरू में रिश्वत के लेनदेन के दौरान दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के आवास पर तलाशी ली। इस दौरान करीब 3.59 करोड़ रुपये नकद, 4 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा और गहने बरामद किए गए। विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर, हांगकांग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, इंडोनेशियाई रुपया, मलयेशियाई रिंगिट, यूरो, युआन, स्वीडिश क्रोना और दिरहम शामिल हैं। साथ ही कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान एक कमरे में तीन बड़े सूटकेस मिले। जब इन्हें खोला गया तो सभी सूटकेस नकदी से भरे हुए थे। शुरूआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि आरोपी अधिकारी लंबे समय से भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल था और अपने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा था। सीबीआई का कहना है कि संयुक्त निदेशक ने संस्थान की जिम्मेदारियों का गलत इस्तेमाल किया और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। निजी कंपनी के उत्पादों को मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत ली जा रही थी। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस भ्रष्टाचार नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था और इससे पहले कितनी बार इस तरह के लेनदेन हुए। सीबीआई ने संकेत दिए हैं कि मामले की जांच अभी शुरूआती चरण में है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख रही हैं

(लेखक- प्रहलाद सबनानी)

अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि ब्रिक्स संगठन के सक्रिय सदस्य देशों - भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन - एवं कुछ अन्य देशों पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करते हुए इसे अमेरिकी संसद में पारित कराने हेतु भेज दिया है। दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं लम्बित हैं जिनमें डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले उत्पादों के आयात पर लागू किए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। संभवतः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना निर्णय दिनांक 9 जनवरी 2025 को दिया जा सकता है। यदि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ट्रम्प के खिलाफ आता है तो ट्रम्प अपने पास टैरिफ को लागू करने सम्बंधी अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाए जाने सम्बंधी प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया है। घोषित तौर पर तो ट्रम्प द्वारा भारत और चीन द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह दोनों देश रूस से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं और इस संदर्भ में ट्रम्प द्वारा दी जा रही चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परंतु, वास्तव में ट्रम्प ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों, विशेष रूप से भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन से बहुत परेशान है, क्योंकि यह देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही, यह देश अपने विदेशी व्यापार के भुगतान को अमेरिकी डॉलर के स्थान पर अपनी अपनी मुद्राओं में करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों के बीच होने वाले व्यापार के भुगतान का निपटान करने हेतु ब्रिक्स मुद्रा को लाने का प्रयास भी इन देशों द्वारा किया जा रहा है। इससे निश्चित ही वैश्विक स्तर पर डीडोलराईजेशन की प्रक्रिया तेज होगी। इससे अमेरिका की चौधराहट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः ट्रम्प उक्त चारों देशों से बहुत अधिक नाराज है एवं इन चारों देशों को सबक सिखाना चाहते है।

परंतु, अब ट्रम्प को वैश्विक स्तर पर हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। भारत, रूस, ब्राजील एवं चीन आज विश्व के शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हैं। यह देश वेनेजुएला जैसे छोटे देश नहीं हैं जिन पर ट्रम्प अपना अधिकार एवं अपनी चौधराहट जता पाए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित ट्रम्प की सेना द्वारा रात्रि को सोते समय गिरफ्तार कर अमेरिका में ले जाया गया है। इसके बाद से ट्रम्प द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि वेनेजुएला स्थित तेल के कुओं से कच्चे तेल के भंडार को अब अमेरिकी कम्पनियों द्वारा निकाला जाएगा एवं इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा और इस व्यवहार से होने वाले लाभ पर अमेरिका एवं वेनेजुएला का अधिकार होगा। यह तो संप्रुभता सम्पन्न राष्ट्र के अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। वास्तव में अमेरिका की वेनेजुएला में कच्चे तेल एवं मूल्यवान खनिज पदार्थों के भंडार पर नजर है एवं इन्हें वह अपने कब्जे में लेना चाहता है इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में लाया गया है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी प्रकार, अब ग्रीनलैंड नामक द्वीप जिस पर इस समय डेनमार्क का अधिकार है, को भी अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका के पास पहिले से ही ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा 'पिटुफिक स्पेस बेस' है। परंतु, ट्रम्प यह पूरा द्वीप ही अमेरिकी कब्जे में लाना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस द्वीप की उन्हें जरूरत है। वेनेजुएला को हथियाने के तुरंत बाद ट्रम्प ने वेनेजुएला के पश्चिमी पड़ौसी देश कोलम्बिया जहां तेल के विशाल भंडार है तथा सोना, चांदी, पन्ना प्लेटिनम और कोयले की भारी मात्रा में खदाने हैं, को भी चेतावनी दे दी है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर इतनी सख्ती नहीं की जानी चाहिए कि प्रदर्शन करने वाले नागरिकों की मौत ही हो जाए। अन्यथा, अमेरिका को इस स्थिति से निपटने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ईरान भी इस समय बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है और ट्रम्प ने ईरान को भी चेतावनी दे डाली है कि ईरान में अगर और अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो अमेरिका को कठोर जवाब देना होगा।

मेक्सिको पर भी अमेरिका की टेड़ी दृष्टि पड़ रही है और अमेरिका का सोचना है कि मेक्सिको से अमरीका में ड्रग्स एवं अवैध अप्रवासियों का आना जारी है। अमेरिका का कहना है कि इसे यदि मेक्सिको प्रशासन द्वारा रोका नहीं गया तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहिले दिन ही ट्रम्प ने 'गल्फ आफ मेक्सिको' का नाम बदलकर 'गल्फ आफ अमेरिका' करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2016 में अपने पहिले कार्यकाल के दौरान भी ट्रम्प ने मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर एक दीवार बनाने का बयान दिया था।

मेक्सिको पर भी अमेरिका की टेड़ी दृष्टि पड़ रही है और अमेरिका का सोचना है कि मेक्सिको से अमरीका में ड्रग्स एवं अवैध अप्रवासियों का आना जारी है। अमेरिका का कहना है कि इसे यदि मेक्सिको प्रशासन द्वारा रोका नहीं गया तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहिले दिन ही ट्रम्प ने 'गल्फ आफ मेक्सिको' का नाम बदलकर 'गल्फआफ अमेरिका' करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

क्यूबा के वेनेजुएला के साथ घनिष्ठ सम्बंध रहे हैं। वेनेजुएला द्वारा कथित तौर पर क्यूबा को लगभग 30 प्रतिशत तेल की आपूर्ति की जाती रही है, इसके बदले में क्यूबा, वेनेजुएला को डॉक्टर एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध कराता रहा है। क्यूबा, फ्लोरिडा (अमेरिका) से केवल 90 मील दक्षिण स्थित द्वीप है और 1960 के दशक की शुरुआत से ही अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। परंतु, अब क्यूबा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के पश्चात, तेल की आपूर्ति ठप्प होने के चलते मुश्किलों से घिर गया है और इसे अब अमेरिका पर निर्भर रहना ही होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां लम्बे समय से चली आ रही है एवं अमेरिका अभी तक के अपने इतिहास में अन्य देशों पर हस्तक्षेप जैसे सैकड़ों मामलों में शामिल रहा है। वर्ष 1776 से वर्ष 2026 के बीच अमेरिका लगभग 400 हस्तक्षेपों में शामिल रहा है। इसमें से लगभग 200 हस्तक्षेप वर्ष 1950 के बाद के खंडकाल में हुए हैं। वर्तमान समय में भी अमेरिका 5 अलग अलग युद्धों में सार्वजनिक रूप से ज्ञात सैन्य अभियानों में शामिल है। सोमालिया, सीरिया और यमन में हो रहे युद्धों में अमेरिका अपने आप को, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शामिल होना बताता है और वेनेजुएला में मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध में शामिल होना बताता है। इसी प्रकार अमेरिका रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध, इजराईल हम्मास के बीच चल रहे युद्ध एवं कम्बोडिया थाईलैंड के बीच हुए युद्ध में भी अपनी चौधराहट दिखाता रहता है। अमेरिका द्वारा अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया जाना सामान्य सी बात है। अभी हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कराने में भी अमेरिका का हाथ बताया जाता है। अमेरिका द्वारा इन हस्तक्षेपों को जिन कारणों से उचित ठहराया जाता है, उनमें शामिल हैं - आतंकवाद विरोधी अभियान, शासन परिवर्तन, क्षेत्रीय विस्तार, अमेरिकी नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा, आर्थिक अवसर, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करना, आदि है। अमेरिका की विदेश नीति की हस्तक्षेपवाद मुख्य विचारधारा रही है। इसी नीति के तहत अमेरिका की नजर वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, कोलम्बिया, ईरान, क्यूबा, मेक्सिको एवं नाईजेरिया में भी हस्तक्षेप करने की नजर आती है।

यूरोप के 7 देशों (फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन एवं डेनमार्क) ने अमेरिका को गम्भीर चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका द्वारा कोई सैनिक कार्यवाही की गई तो इसके गम्भीर परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे और बहुत सम्भव है कि इस कार्यवाही के बाद यूरोपीय देशों एवं अमेरिका का संयुक्त नाटो संगठन ही बिखर जाए। नाटो संगठन के सदस्य देशों के बीच यह समझौता है कि इस संगठन के किसी भी एक सदस्य पर यदि सैन्य हमला होता है तो यह सैन्य हमला समस्त सदस्य देशों पर माना जाएगा और समस्त सदस्य देश मिलकर इस सैन्य हमले का जवाब देंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने दिनांक 7 जनवरी 2026 को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने की जानकारी प्रदान की है। इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं शामिल हैं। ट्रम्प का सोचना है कि इन संगठनों की सदस्यता के चलते अमेरिकी हितों के अनदेखी हो रही है और इससे अमेरिकी पैसे की बर्बादी हो रही है। अमेरिका का यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा माना जा रहा है और वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका को दूर ले जाने का प्रयास है।

वैश्विक स्तर पर अब आर्थिक सत्ता का केंद्र पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर स्थानांतरित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रम्प अपने क्रियाकलापों से इसे गति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ब्रिक्स के सदस्य देशों में 325 करोड़ नागरिक निवास करते हैं और यह विश्व की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है। साथ ही, इन देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 39 प्रतिशत की भागीदारी है, जबकि जी-7 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 29 प्रतिशत ही है। अतः आज विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों की अनदेखी करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अमेरिका केवल अपने दम पर कितने दिन चल सकता है, वह आज भी कई उत्पादों के लिए अन्य देशों पर पूर्णतः निर्भर है। आज की वैश्विक व्यवस्था में जब विभिन्न देश विभिन्न कारणों से एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसे में अमेरिका द्वारा विश्व के कई शक्तिशाली देशों के साथ अपने सम्बन्धों को खराब करना, अमेरिका के हितों के विपरीत तो है ही, साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इसे अमेरिकी नागरिकों को तो समझना ही होगा।

(सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के-8, चेतकपुरी कालोनी, झांसी रोड, लश्कर, ग्वालियर)

संपादकीय

गंदे व बदबूदार पानी

यह विडंबना ही है कि हमारे नागरिक प्रशासन का नियामक तंत्र आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से मुक्त नहीं होता। यदि समय रहते संवेदनशील या फिर घातक साबित होने वाली स्थिति व परिस्थिति पर नजर रखी जाए तो जनधन की हानि टाली भी जा सकती है। हाल ही में दूषित पेयजल से इंदौर में हुई जन हानि के बाद रोहतक और झज्जर की उन चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती,जिसमें नागरिक घरों में आने वाले गंदे व बदबूदार पानी की शिकायत करते रहे हैं। निश्चय ही इस स्थिति को जन स्वास्थ्य से जुड़े आपातकाल के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही नागरिकों की शिकायत की जांच-पड़ताल कर अविलंब कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जवाबदेही न निभाने और एक-दूसरे विभाग पर दोष मढ़ने का पुराना सिलसिला ही अकसर सामने आता है। उल्लेखनीय है कि इंदौर की हालिया दूषित पेयजल की त्रासदी में नगरपालिका द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी के सेवन से कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विडंबना यह है कि वहां भी नागरिकों की शुरुआती चेतावनियों को सामान्य शिकायतों के रूप में देखकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इंदौर में पेयजल पाइपलाइनों में सीवेज का रिसाव हुआ था। यह स्वीकारोक्ति भी तब सामने आई जब बड़ा नुकसान हो चुका था। लगता है कि रोहतक व झज्जर भी इसी तरह के आसन्न खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आने वाले ऐसे मामले न तो रहस्यमय हैं और न ही ये कोई नई बात ही है। बुनियादी ढांचागत व्यवस्था का जर्जर होना, सीवर लाइनों में रिसाव, अनियोजित शहरी विस्तार और नागरिक एजेंसियों के बीच आवश्यक समन्वय का अभाव, अकसर ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, जहां सीवेज और पीने का पानी खतरनाक रूप से एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। गाहे-बगाहे देश के विभिन्न भागों में स्थानीय नागरिक जब-तब आरोप लगाते हैं कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिलने की आशंका है। ऐसे में शासन-प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया, इसके सत्यापन, पाइप लाइन की मरम्मत और वैकल्पिक पेयजल उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य संकट को दूर करने और अपनी बात मनवाने के लिये यदि नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है तो यह शासन-प्रशासन की विफलता को ही दर्शाता है। विडंबना यह है कि जल प्रदूषण का सबसे बुरा असर समाज के कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इसकी चपेट में आते हैं। निर्विवाद रूप से दूषित जल से डायरिया, हेपेटाइटिस और अन्य दूषित जल जनित बीमारियों का प्रभाव तेजी से फैलता है। जिसके चलते अफरा-तफरी के बीच अक्सर स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में तंत्र की निष्क्रियता की कीमत आम लोगों को न केवल अस्पताल के भारी-भरकम बिलों के रूप में, बल्कि जानमाल के नुकसान और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में आई कमी के रूप में भी चुकानी पड़ती है। निश्चित रूप से दूषित पाइपलाइनों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। व्यापक स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में जल स्रोतों का परीक्षण होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लिए गए पानी के नमूनों की जांच के परिणाम भी सार्वजनिक किए जाएं। इसके अलावा आवश्यक है कि दूषित सिस्टम के सुरक्षित प्रमाणित होने तक सुरक्षित वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैंकों से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा केंद्र सरकार को- घटता कर-संग्रह, बढ़ता कर्ज और 2026-27 का बजट?

(लेखक - सोहिल जैन)

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है। जहां सरकार के सामने विकल्प कम और चुनौतियां अधिक हैं। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पिछले वर्षों के मुकाबले कम वृद्धि है। कर राजस्व में लगातार कमी होने से केंद्र और राज्य—दोनों सरकारों की वित्तीय स्थिति को गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आमतौर पर भारत में टैक्स कलेक्शन हर साल 10 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में यह वृद्धि 7 प्रतिशत से भी नीचे आती दिख रही है। यह संकेत मिलता है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होती जा रही है। मांग और खपत में वह मजबूती नहीं है, जिसकी उम्मीद सरकार कर रही थी।

सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी स्लैब में कटौती करके मांग और आपूर्ति को बढ़ाने का कदम उठाया था। लेकिन सरकार की इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिली। सवाल यह है कि जब लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, तो टैक्स छूट का लाभ किसे मिलेगा? बड़ी आबादी आज संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है। इसमें अस्थायी नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। जहां आय कम है, अनिश्चित आय,सामाजिक सुरक्षा लगभग न के बराबर है। ऐसे में उपभोक्ता खर्च कैसे बढ़ेगा? यही कारण है, त्योहारों के मौसम के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में वह वृद्धि नजर नहीं आई, जिसका दावा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा था।

इस कमजोर कर-संग्रह ने सरकारों को चिंता में डालकर वैकल्पिक रास्तों को खोजने की दिशा मे धकेल दिया है।

रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा एक नया फैसला लिया गया है इसके अनुसार बैंकों के डिविडेंड वितरण से जुड़े नियमों में जो बदलाव किया है। वह इसी मजबूरी का नतीजा है। अब बैंकों को अपने मुनाफे का 75 प्रतिशत डिविडेंड देने की अनुमति की तैयारी की जा रही है। अभी यह सीमा 40 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी अधिक है, इसलिए इस बदलाव से सरकारी खजाने को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। राजस्व संग्रह में जो कमी आएगी। केंद्र सरकार इससे अपना खजाना भरेगी। यह राहत अल्पकालिक है। इससे बैंकों की पूंजीगत मजबूती कमजोर होगी। बैंकों की ऋण देने की क्षमता प्रभावित होगी। भविष्य में किसी संकट से निपटने में बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। यह परिवर्तन वित्तीय अनुशासन से ज्यादा राजकोषीय घाटे के दबाव को दर्शाता है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की आर्थिक हालत भी चिंताजनक है। राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी है,अगर बैंकों से कर्ज लेने की क्षमता यदि वर्तमान में जो है वही रहेगी। तो वह कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो सकते हैं। केंद्र और राज्यों की संयुक्त उधारी 25 से 30 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई है। इतना बड़ा कर्ज केंद्र एवं राज्य सरकारों के बजट एवं भविष्य की पीढ़ियों पर भारी बोझ डालने वाला है।

सरकार के लिए सबसे आसान रास्ता अप्रत्यक्ष कर बढ़ाना होता है। यही कारण है, पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार समय-समय पर बढ़ोतरी करती है। इसका लाभ केंद्र सरकार को राजस्व के रूप मे मिलता है। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका बोझ अंततः आम उपभोक्ता पर आता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है, जिसमें कर बढ़ने से खपत और कमजोर होती है। खपत कमजोर होने से कर-संग्रह और भी घट जाता है।

1 फरवरी को केंद्र सरकार का 2026-27 का बजट पेश होने जा रहा है, सरकार के सामने राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ओर केंद्र एवं राज्य सरकारों पर ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ रहा है, कुल टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा ब्याज एवं कर्ज के भुगतान की देनदारी में जा रहा है। दूसरी ओर विकास व सामाजिक योजनाओं के लिए सरकार के पास बजट में पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार केवल अल्पकालिक उपायों—जैसे डिविडेंड बढ़ाना, डिसइन्वेस्टमेंट और एक्साइज ड्यूटी—पर निर्भर रहेगी, या रोजगार सृजन की आय बढ़ाने और स्थायी मांग पैदा करने की ठोस रणनीति अपनाएगी?

यह बजट केवल संख्याओं का खेल नहीं होना चाहिए। यह तय करेगा भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग और कर्ज के सहारे आगे बढ़ेगी या उत्पादन, रोजगार और आय के मजबूत आधार पर आगे बढ़ेगी। मूल समस्या लोगों की आय और सुरक्षित रोजगार का समाधान का प्रावधान इस बजट में किया जाना चाहिए। अन्यथा कर-संग्रह बढ़ाने के सारे प्रयास अंततः विफल साबित हो सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने बजट में गंभीरता से ध्यान देना होगा। अन्यथा आने वाला समय केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा।

सिद्धांत गौण है, सत्ता प्रमुख

पिछले दिनों में राष्ट्रीय रंगमंच पर जिस प्रकार का राजनीतिक चरित्र उभरकर आ रहा है, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है, राजनीति का अर्थ देश में सुव्यवस्था बनाए रखना नहीं, अपनी सत्ता और कुर्सी बनाए रखना है। राजनीतिज्ञ का अर्थ उस नीति-निपुण व्यक्तित्व से नहीं है, जो हर कीमत पर राष्ट्र की प्रगति, विकास-विस्तार और समृद्धि को सर्वोपरी महत्व दे; किंतु उस विदूषक-विशारद व्यक्तित्व से है, जो राष्ट्र के विकास और समृद्धि को अवनति के गर्त में फेंककर भी अपनी कुर्सी को सर्वोपरि महत्व देता हो। राजनेता का अर्थ राष्ट्र को गति की दिशा में अग्रसर करने वाला नहीं, अपने दल को सत्ता की ओर अग्रसर करने वाला रह गया है। यही कारण है कि आज राष्ट्र गौण है, दल प्रमुख है। सिद्धांत गौण है, सत्ता प्रमुख है। चरित्र गौण है, कुर्सी प्रमुख है।

एक राजनेता में राष्ट्रीय चरित्र, न्याय-सिद्धांत और नेतृत्व क्षमता के गुणों की आवश्यकता नहीं, किंतु आज कुशल राजनेता वही है, जो अपने दल के लिए राष्ट्र के साथ भी विश्वासघात कर सकता हो, अपनी कुर्सी के लिए अपने दल के साथ भी विश्वासघात करने का जिसमें साहस या दुस्साहस हो।

बहुत बार मन में प्रश्न उभरता है, क्या राजनीति का अपना कोई चरित्र नहीं होता अथवा सत्ता प्राप्ति के लिए राष्ट्र, समाज, दल और व्यक्ति की विश्वासपूर्ण भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ही राजनीति का चरित्र होता है? जनता की कोमल भावनाओं का शोषण करके सत्तासीन होने के बाद क्या राजनेता का व्यक्तित्व जनता और राष्ट्र से भी बड़ा हो जाता है?

यदि ऐसा नहीं है तो आज की राजनीति क्यों अपने प्रिय पुत्रों, संबंधियों और चमचों-चाटुकारों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गई है? राष्ट्र को स्थिर नेतृत्व प्रदान करने के नाम पर क्यों सिद्धांतहीन समझौते और स्तरहीन कलाबाजियां दिखाई जा रही हैं? संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद को भड़का करके क्यों सत्ता की गोटियां बिठाई जा रही हैं? आज की राजनीति को देखकर मन ग्लानि और वितृष्णा से भर जाता है। आखिर यह सबकुछ कब तक चलता रहेगा?

विचार मंथन

घटता कर-संग्रह 2026-27 के बजट की चुनौती?

(लेखक - सनत जैन/)

देश का आर्थिक परिदृश्य इस समय गंभीर दौर से गुजर रहा है। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट ने केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आमतौर पर भारत में पिछले 30 वर्षों से टैक्स कलेक्शन 10-15 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहा है, हालिया आंकड़े बताते हैं, यह वृद्धि अब 7 प्रतिशत से नीचे फिसलती हुई दिख रही है। यह स्थिति केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति की वास्तविक हकीकत है। लोगों की जेब में खर्च करने के लिए अब पैसा नहीं है। कर्ज का बोझ अधिक होने के कारण अब नया कर्ज भी नहीं मिल रहा है। बचत पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को सीमित खर्चे में अपना जीवन-यापन करना पड़ रहा है। सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी स्लैब में कटौती की। इसके बाद भी बाजार में इसका अपेक्षित असर नहीं दिख रहा है। मूल समस्या लोगों की आय सीमित है। महंगाई बढ़ती जा रही है। जिसके कारण कर छूट का फायदा भी आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब रोजगार स्थायी नहीं होंगे, आय में वृद्धि नहीं होगी, तब तक उपभोग बढ़ने की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। गिग इकोनॉमी के बढ़ते दायरे ने रोजगार के आंकड़े सुधारे हैं, लेकिन इससे बहुत कम आय लोगों को हो रही है। इस काम में भी अस्थिरता होने के कारण लोगों की क्रयशक्ति में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। आर्थिक स्थिति की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का संकट और भी गहरा होता जा रहा है। इस वित्तीय दबाव के बीच सरकार की नजर अब गैर-कर स्रोतों पर टिक गई है। बैंकों के लिए डिविडेंड वितरण की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव इसी मजबूरी को दर्शाता है। इससे केंद्र सरकार को अपने राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अल्पकाल के लिए सरकार को राजस्व मिलेगा, लेकिन रिजर्व बैंक और सरकार के इस परिवर्तन से बैंकों की पूंजीगत मजबूती और भविष्य की आर्थिक स्थिरता पर गंभीर संकट जल्द ही देखने को मिल सकता है। यह ऐसा ही है, जैसे आज की जरूरत के लिए जमा पूंजी और बचत को गिरवी रखना या खर्च कर देना है। केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है। बढ़ता कर्ज, वेतन और ब्याज भुगतान का बोझ, और सीमित राजस्व ने राज्यों को कर्ज के मकड़जाल में फंसा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना केंद्र सरकार के लिए आसान विकल्प है। इसका फायदा राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा 40 फ़ीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकारों पर डाल देने से राज्यों की आर्थिक स्थिति में गंभीर संकट आने वाला है या तो मनरेगा जैसी योजनाएं नाम बदलने के बाद बंद होंगी। इसका सीधा असर रोजगार और महंगाई के रूप में आम जनता पर पड़ना तय है। 2026-27 के बजट में सरकार के पास राजस्व में वृद्धि करने के विकल्प सीमित हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर खर्च और योजनाओं को चलाने के लिए आय में निरंतर खाई बढ़ती चली जा रही है। आगामी बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। बजट आर्थिक दिशा तय करने की कसौटी होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारें 2026-27 के बजट में केंद्र एवं राज्य सरकारें जो प्रावधान करेगी, वह कसौटी में कितने खरे उतरेंगे यह कहना मुश्किल है। सवाल साफ है, क्या सरकारें तात्कालिक राहत के लिए दीर्घकालिक स्थिरता को दांव पर लगाएगी, या रोजगार, आय और मांग बढ़ाने की ठोस रणनीति आगामी बजट में अपनाएगी? जिस तरह से राज्यों के ऊपर निरंतर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है उनकी आय पिछले वर्षों की तुलना में नहीं बढ़ रही है। खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का राजस्व राज्यों में घट रहा है। केंद्र सरकार सेस और शुल्क बढ़ाकर अपने राजस्व में तो किसी तरह से वृद्धि कर पा रही है, लेकिन राज्यों के पास कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किस दिशा की ओर जाएगी कहना मुश्किल है। पिछले एक दशक में जिस तरह से सरकार ने अपने खर्च बढ़ाये हैं। नई-नई योजनाएं लागू की है। अब इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट केंद्र एवं राज्य सरकार तैयार कर रही हैं। उन चुनौतियों से किस तरह से निपटेंगी इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

आरबीआई के यूडीजीएएम पोर्टल से घर बैठे चेक करें अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट

नई दिल्ली ।

अक्सर लोग सोचते हैं कि सालों तक इस्तेमाल न होने पर बैंक खाते का पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में जमा राशि सुरक्षित रहती है और उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट में दर्ज किया जाता है। ऐसे पैसे को खाताधारक या उनके वारिस कभी भी क्लेम कर सकते हैं। आरबीआई ने इस समस्या को आसान बनाने के लिए अनक्लेम्ड` डिपो जिट गेटवे टू एसेस इंफारमेशन (यूडीजीएएम) पोर्टल लॉन्च किया है। अब अलग-अलग बैंकों की शाखाओं में जाने की बजाय घर बैठे यह पता लगाया जा सकता है कि आपके या परिवार के नाम पर कोई राशि अनक्लेम्ड है या नहीं। पोर्टल पर नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें। पुराने रिकॉर्ड में नाम अलग तरीके से दर्ज हो सकता है, इसलिए अलग-अलग स्पेलिंग से सर्च करना बेहतर होता है। अगर पोर्टल पर एंट्री मिलती है, तो बैंक से संपर्क करें। खाताधारक आसानी से क्लेम कर सकता है। कानूनी वारिस के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। 10 साल बाद भी पैसा आरबीआई के डीईएएफ में ट्रांसफर होने के बाद क्लेम किया जा सकता है।

आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बैंकिंग में पारदर्शिता और विश्वास पर जोर दिया

मुंबई ।

डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने कहा कि बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की कीमत और शर्तें ग्राहकों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता नहीं होगी, तो ग्राहक अन्य विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। शंकर ने बैंकिंग उद्योग से आग्रह किया कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जहां कोई धोखाधड़ी न हो ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का भरोसा ही उन्हें बैंकिंग प्रणाली के प्रति वफादार बनाए रखने की कुंजी है। प्रभावी मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ग्राहक जो मूल्य चुका रहे हैं, वह उचित और सही है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत है, लेकिन ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर- शक्तिकांत दास

सरकार की नीतियां और सुधार भारत को मजबूत बनाने में कर रही हैं मदद

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत आज ऐतिहासिक यात्रा की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने पहला विवेक देवराय स्मृति व्याख्यान देते हुए वैश्वीकरण के पिछले दशकों में गति देने वाली आम सहमति के कमजोर पड़ने और बहुपक्षीय सहयोग में कठिनाइयों का जिक्र किया। दास ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब अलग-थलग पड़ना नहीं है। यह आर्थिक लचीलापन और क्षमता विकसित करने की रणनीति है। इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के घरेलू उत्पादन की क्षमता बढ़ाना और विदेशी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और सुधार भारत को मजबूत, लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रही हैं। दास के अनुसार यह दृष्टिकोण न केवल मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहायक है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में भी निर्णायक है।

टोयोटा की कारों की कीमतों में बढ़ोतरी, भारतीय ग्राहकों पर पड़ेगा असर

फॉर्च्यूनर के वेरिएंट की कीमतें 51,000 से लेकर 74,000 तक बढ़ी

मुंबई । भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हाल ही में टोयोटा ने अपनी प्रमुख कारों- फॉर्च्यूनर और इनोवा की कीमतों में वृद्धि की है। फॉर्च्यूनर के वेरिएंट की कीमतों में 51,000 रुपये से लेकर 74,000 रुपये तक का इज़ाफ़ा देखा गया है। बेस 4 गु णित 2 एमटी पेट्रोल वेरिएंट अब 34.16 लाख रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले यह 33.65 लाख रुपये थी। 4 गु णित 4 लाइनअप की कीमत 38.68 लाख रुपये से शुरू होती है, जो पहले 38.11 लाख रुपये थी। 4 गु णित 2 एटी लीजेंडर वेरिएंट में 63,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 42.17 लाख रुपये में उपलब्ध है। फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव 4 गु णित 4 एटी वेरिएंट की कीमत 42.37 लाख रुपये हो गई है, वहीं 4 गु णित 4 एमटी लीजेंडर अब 44.30 लाख रुपये में उपलब्ध है। टॉप-स्पेक जीआरएस वेरिएंट अब 49.59 लाख रुपये का हो गया है। टोयोटा ने इस लाइनअप में कुछ सीमित संस्करण जैसे लीडर वेरिएंट को भी बंद कर दिया है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के बेस जीएक्स 7 सीटर और 8 सीटर वेरिएंट को बंद कर दिया गया है। नया बेस जीएक्स 7

सीटर अब 19.15 लाख रुपये में उपलब्ध है, जो पहले 18.86 लाख रुपये था। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वीएक्स वेरिएंट की कीमत में 40,000 रुपये की वृद्धि हुई है। टॉप वेरिएंट जीएक्स 7 सीटर अब 46,000 रुपये महंगा हो गया है, जबकि जेड एक्स (ओ) एलई 7 सीटर की कीमत 32.38 लाख रुपये तक बढ़ गई है।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार, उत्पादन लागत में वृद्धि और बढ़ती मांग के कारण यह कीमतों का सामान्य रुझान है।

आरबीआई का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड निवेश घटकर 190 अरब डॉलर हुआ

चीन, ब्राजील, सऊदी अरब और हांगकांग ने भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी घटाई

नई दिल्ली । अक्टूबर 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश लगभग 190 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल के मुकाबले 50.7 अरब डॉलर कम है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी और अन्य विकसित देशों में बढ़ते वित्तीय दबावों के कारण बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हुई है, जिससे ट्रेजरी बॉन्ड में वैल्यूएशन लॉस का जोखिम बढ़ गया। इसी अवधि में आरबीआई ने अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है। अक्टूबर 2025 तक केंद्रीय बैंक के पास 880.18 मीट्रिक टन सोना था, जो पिछले साल 866.8 टन था। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 13.6 फीसदी हो गई, जबकि पिछली बार यह 9.3 फीसदी थी। भारत ही नहीं, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब और हांगकांग ने भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। विशेषज्ञों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता कम कर सुरक्षित एसेट जैसे सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

केंद्र सरकार ग्रोक पर कानूनी कार्रवाई पर कर रही विचार

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा समीक्षा

नई दिल्ली

। केंद्र सरकार ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाले एआई चैटबॉट ग्रोक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। यह कदम ग्रोक द्वारा महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के मामलों के कारण उठाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रोक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट की तरह सामग्री तैयार करता है, और अगर यह गैरकानूनी है तो इसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ग्रोक का तस्वीर बनाने का फीचर अब केवल भुगतान करने वाले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं तक सीमित है,

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि जब तक एक्स (पूर्व में ट्विटर) इसे भारत की आधिकारिक नीति के रूप में नहीं अपनाता, तब तक कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजकर पूछा था कि ग्रोक ने महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक सामग्री बनाने की अनुमति कैसे दी। इस नोटिस के जवाब में एक्स ने जो विवरण भेजा, वह अधिकारियों को संतोषजनक नहीं लगा।

उन्होंने कहा कि इसमें उन कदमों का उल्लेख नहीं था जो प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उठाए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को पत्र लिखा कि समयसीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाया जाए और साक्ष्यों को प्रभावित न किया जाए। इसके एक दिन बाद ईलॉन मस्क ने चेतावनी दी कि ग्रोक का उपयोग करके गैरकानूनी सामग्री बनाने वालों को उसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसे अवैध सामग्री अपलोड करने वालों को भुगतने पड़ते हैं।

भारतीय शेयर बाजार में तीन महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट

विदेशी निधियों की लगातार निकासी ने भी बाजार की कमजोरी को और गहरा किया

मुंबई ।

बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार ने तीन महीने में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, जिससे निवेशकों के बीच भारी निराशा और अनिश्चितता देखने को मिली। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की संभावित चेतावनी, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दबाव, तथा प्रमुख ब्लू-चिप शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर लगातार दबाव बनाए रखा। विदेशी निधियों की लगातार निकासी ने भी बाजार की कमजोरी को और गहरा किया। इस दबाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमशः 1.84 फीसदी और 1.71 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को लाल निशान के साथ हुई, जब बीएसई सेंसेक्स 125.96 अंक गिरकर 85,636.05 पर खुला और अंततः 322.39 अंक की गिरावट के साथ 85,439.62 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 30.95 अंक गिरकर 26,297.60 पर खुला और सप्ताह की शुरुआत में 84.50 अंक की गिरावट के साथ 26,250.30 पर बंद हुआ। मंगलवार को बाजार में गिरावट और तेज़ हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स 431.95 अंक गिरकर 85,007.67 पर खुला और 376.28 अंक की गिरावट के साथ 85,063.34 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 105.6 अंक की गिरावट के साथ 26,144.70 पर खुला और अंततः 71.60 अंक घटकर 26,178.70 पर बंद हुआ। बुधवार और गुरुवार को भी गिरावट का क्रम जारी रहा। गुरुवार को सेंसेक्स 780.18 अंक की गिरावट के साथ 84,180.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 263.90 अंक गिरकर 25,876.85 पर बंद हुआ। शुक्रवार को सप्ताह का समापन भी लाल निशान के साथ हुआ, सेंसेक्स 604.72 अंक गिरकर 83,576.24 पर और निफ्टी 193.55 अंक गिरकर 25,683.30 पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों का कहना है ` कि सप्ताह भर का प्रदर्शन यह संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों की निकासी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और अमेरिका के संभावित टैरिफ वृद्धि की आशंका ने बाजार को दबाव में रखा।

केंद्र सरकार ग्रोक पर कानूनी कार्रवाई पर कर रही विचार

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा समीक्षा

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ईलॉन मस्क के स्वामित्व वाले एआई चैटबॉट ग्रोक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। यह कदम ग्रोक द्वारा महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के मामलों के कारण उठाया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रोक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट की तरह सामग्री तैयार करता है, और अगर यह गैरकानूनी है तो इसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ग्रोक का तस्वीर बनाने का फीचर अब केवल भुगतान करने वाले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं तक सीमित है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि जब तक एक्स (पूर्व में ट्विटर) इसे भारत की आधिकारिक नीति के रूप में नहीं अपनाता, तब तक कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजकर पूछा था कि ग्रोक ने महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक सामग्री बनाने की अनुमति कैसे दी। इस नोटिस के जवाब में एक्स ने जो विवरण भेजा, वह अधिकारियों को संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इसमें उन कदमों का उल्लेख नहीं था जो प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उठाए।

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को पत्र लिखा कि समयसीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाया जाए और साक्ष्यों को प्रभावित न किया जाए। इसके एक दिन बाद ईलॉन मस्क ने चेतावनी दी कि ग्रोक का उपयोग करके गैरकानूनी सामग्री बनाने वालों को उसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे जैसे अवैध सामग्री अपलोड करने वालों को भुगतने पड़ते हैं।

दार्जिलिंग चाय का उत्पादन 2025 में घटने की संभावना

नई दिल्ली ।

दार्जिलिंग की मशहूर चाय का उत्पादन 2025 में घट सकता है। चाय बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार, जनवरी से नवंबर तक उत्पादन 51.9 लाख किलोग्राम रहा, जबकि 2024 में इसी अवधि में 56.9 लाख किलोग्राम था। 2024 का कुल उत्पादन 57.1 लाख किलोग्राम था। मौसम के बदलते मिजाज, श्रमिकों की कमी और आर्थिक दबाव मुख्य कारण हैं। चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष सी. मुरुगन ने कहा कि उत्पादन पर नजर रखी जा रही है और अगले महीने तक अंतिम आंकड़े मिल जाएंगे। दार्जिलिंग का उत्पादन 1990 में 1.44 करोड़ किलोग्राम था, लेकिन लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2017 में गोरखालैंड आंदोलन के कारण 104 दिन उद्योग बंद रहने से उत्पादन केवल 32 लाख किलोग्राम रह गया था। लगभग 80-90 फीसदी बागान 70 साल से अधिक पुराने हैं। कई बागानों ने जैविक उत्पादन अपनाया, जिससे उत्पादन में कमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दार्जिलिंग चाय की गिरावट कोई नई बात नहीं है, और यह लंबे समय से जारी है।

सीजन की शुरुआत में ही औंधे मुंह गिरे आलू के दाम, किसान बेहाल

मंडियों में भारी आवक से कीमतों पर दबाव

नई दिल्ली ।

सीजन की शुरुआत होते ही देशभर की मंडियों में आलू के दाम तेजी से गिर गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई स्थानों पर किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है। कीमतों में भारी गिरावट से परेशान किसान मजबूरी में अपनी उपज सड़कों पर फेंकने को विवश हैं। थोक बाजार के साथ-साथ खुदरा बाजार में भी आलू सस्ता हो गया है। जानकारों के मुताबिक आलू के दाम गिरने की सबसे बड़ी वजह पिछले साल का भारी स्टॉक है, जो अब भी बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में भरा पड़ा है। इसके अलावा अनुकूल मौसम के चलते इस साल भी आलू की बंपर पैदावार की उम्मीद है। पुराना आलू खराब होने के डर से बाजार में उतारा जा रहा है, वहीं नए आलू की आवक भी लगातार बढ़ रही है। इससे मंडियों में सप्लाई मांग से कहीं अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडी आगरा में आलू के थोक भाव एक महीने में 900-1,250 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 500-650 रुपये रह गए हैं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता मंडी में भाव 1,500-1,550 रुपये से गिरकर 1,100-1,200 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी और दिल्ली की मंडियों में भी भाव 300-900 रुपये प्रति क्विंटल तक लुढ़क गए हैं। मंडियों में कीमतें गिरने का असर खुदरा बाजार पर भी पड़ा है। पिछले महीने जहां आलू 20 से 25 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत 13 से 20 रुपये प्रति किलो रह गई है। मंडियों में साधारण आलू 5-6 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि इस महीने आलू के दाम दबाव में बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आवक घटेगी, अगले महीने से कीमतों में कुछ सुधार की उम्मीद है।

होम लोन इंश्योरेंस में ऑनलाइन विकल्प से बढ़ सकती है सुरक्षा और बचत

- अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं पॉलिसी का सही चुनाव

नई दिल्ली ।

भारत में होम लोन अब केवल एक अल्पकालिक वित्तीय जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि यह एक लंबी अवधि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन चुका है। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के कारण लोन की राशि और अवधि दोनों बढ़ गई हैं, जिसके चलते होम लोन इंश्योरेंस की आवश्यकता भी पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। इस इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता की असमय मृत्यु या अन्य अप्रत्याशित स्थितियों में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आजकल ऑनलाइन होम लोन इंश्योरेंस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। डिजिटल माध्यम से ली जाने वाली पॉलिसियों में प्रीमियम कम होता है और ग्राहकों को शर्तों, कवरेज और लागत की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इससे ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार पॉलिसी का सही चुनाव कर सकते हैं। वहीं बैंक और अन्य लेंडर्स द्वारा ऑफलाइन पॉलिसी की पेशकश की जाती है, जो अक्सर उच्च प्रीमियम, कमीशन और प्रशासनिक खर्चों के साथ होती है। इसके अलावा, ऑफलाइन पॉलिसी में लचीलापन की कमी और क्लेम की राशि का सीधे बैंक को मिलना जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि होम लोन इंश्योरेंस का चुनाव करते समय केवल सुविधा और बैंक की पेशकश पर ध्यान न देकर, लागत, पारदर्शिता और लचीलापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही पॉलिसी परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती देती है और खर्च कम करने में मदद करती है।

वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स के छह प्रमुख कैटेगरी के टॉप फाइनलिस्ट तैयार, 1 अप्रैल को होगा ऐलान

न्यूयॉर्क।

2026 वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल जगत में हलचल तेज हो गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को इस बार बेम्बो के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और शुरुआती चरण में छह प्रमुख कैटेगरी के टॉप फाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं। इन नतीजों को वैश्विक प्रोफेशनल ऑडिट कंपनी केपीएमजी द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत हो जाती है। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल 2026 पर टिकी हैं। इस अवॉर्ड के चयन की प्रक्रिया को दुनिया की सबसे निष्पक्ष प्रक्रियाओं में गिना जाता है। 33 देशों के 98 अनुभवी ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट्स ने इसमें भाग लिया, जिन्होंने कारों को अपने नियमित प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव और रिव्यू अनुभव के आधार पर जांचा। भारत से योगेन्द्र प्रताप भी इस अंतरराष्ट्रीय जूरी का हिस्सा रहे। सभी जजों ने सीक्रेट बैलेट सिस्टम के जरिए वोटिंग की, जिससे किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश नहीं रही। बेम्बो के सीईओ ने इस साल चुनी गई कारों की जमकर तारीफ की है। उनके मुताबिक वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का वैश्विक मानक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की कारें न केवल बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, बल्कि भविष्य की मोबिलिटी की दिशा भी तय करती हैं। वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2026 की मुख्य कैटेगरी में 58 कारों में से टॉप 10 को चुना गया है। इस सूची में ऑडी क्यू5, बीएमडब्ल्यू आईएक्स3, बीवॉयडी सेल 6 डीदएम-आई, हुंडई लोनिक ढ्ढश्ठद्वद्ग 9, हुंडई पालिसेड, किया ईवी4, किया ईवी5, मर्सिटीज बैंज सीएलए, निशान लेफ और टोयोटा आरएवी4 जैसी कारें शामिल हैं। यह सूची इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और पारंपरिक इंजन वाली कारें अब एक ही मंच पर बराबरी से मुकाबला कर रही हैं। इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में ऑडी ए6 ई-टॉर्न, बीएमडब्ल्यू आईएक्स3, हुंडई लोनिक9, मर्सिटीज-बैंज सीएलए और निशान लेफ ने अपनी जगह बनाई है, जो ईवी सेगमेंट की तेजी से बढ़ती ताकत को दर्शाता है। लग्जरी कार कैटेगरी में ऑडी ए6, काडिलिक्स विस्तिक, लुकिड ग्रेवेटी और वॉल्वो ईएस90 जैसे प्रीमियम मॉडल शामिल हैं, जबकि परफॉर्मेंस कैटेगरी में बीएमडब्ल्यू एम2 सीएस, कॉरवैटे ई-राय, डिवेंडर ओसटीए और मर्सिटीज-एएमजी जीटी 63 प्रो जैसी दमदार कारें मुकाबले में हैं।

आईआईएएस ने ग्रो की मूल कंपनी के प्रस्तावों का विरोध किया

सभी पांच प्रस्तावों के खिलाफ वोट की सिफारिश

नई दिल्ली ।

प्रॉक्सी सलाहकार फर्म इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस) ने ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के सभी पांच प्रस्तावों के खिलाफ वोट करने की सिफारिश की है। फर्म ने कहा कि ये प्रस्ताव कॉरपोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। आईआईएएस ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) 2024 के तहत 33.15 करोड़ शेयर ऑप्शंस जारी करने के प्रस्ताव का विरोध किया। फर्म ने कहा कि ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में स्पष्टता नहीं है और यह नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा, ऑप्शन की प्रयोग अवधि असामान्य रूप से लंबी है, वेस्टिंग के बाद 20 साल तक और लिस्टिंग के बाद 10 साल तक। कंपनी ने आ र्टिकल आफ एसो सिएशन में संशोधन कर संस्थापकों को बोर्ड में निदेशक नामित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। आईआइएएस ने बिना न्यूनतम शेयरधारिता सीमा के ऐसे अधिकारों का विरोध किया, जबकि पीक एक्सवी पार्टनर को हिस्सेदारी की शर्त पर यह

अधिकार देने का समर्थन किया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आज से शुरु हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज में कोहली और रोहित आकर्षण का केंद्र

वडोदरा (एजेंसी)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार से तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में होगा। इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड की टीम नए और युवा खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन पूरी ताकत के साथ उतर रही भारतीय टीम के लिए रोहित और कोहली के नजरिये से सीरीज अहम है। अगले महीने वाली टी20 विश्व कप के कारण वनडे सीरीज की अहमियत थोड़ी कम है, लेकिन अगले सात दिनों में होने वाले तीन वनडे मैचों में कोहली और रोहित आकर्षण का केंद्र रहने वाले है।

दोनों दिग्गजों को हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के लीग चरण में अच्छा मैच अभ्यास मिला है। उन्होंने इस घरेलू टूर्नामेंट में बड़े स्कोर बनाकर बता दिया हैं कि उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि टी20 विश्व कप टीम से बाहर होने के बाद कप्तान शुभमन गिल कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी फॉर्म पहले से ही चिंता का विषय रही है, वहीं पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में वे चोट के कारण बाहर रहे थे। गिल की वापसी से यशस्वी जायसवाल को शीर्ष क्रम से बाहर बैठना पड़ सकता है। जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में अपना पहला वनडे शतक जमाया था।

वहीं श्रेयस अय्यर की वापसी से बल्लेबाजी क्रम में चल रहे प्रयोगों पर विराम लग सकता है। क्योंकि श्रेयस का चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना लगभग तय है। केएल राहुल की निचले क्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में भूमिका जारी रहने से ऋषभ पंत के अंतिम एकादश में शामिल होने की संभावना कम होती दिख रही है। अय्यर, पंत और मोहम्मद सिराज विजय हजारे ट्रॉफी में व्यस्तता के कारण वनडे टीम की यहां चल रही तैयारियों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पूरे दमखम के साथ अभ्यास किया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। इसके बाद तेज गेंदबाजी का दारोमदार मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा पर होगा। कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले है। शाम की ओस और सपाट पिचों की प्रकृति को देखकर प्रारूप में आक्रामक विकेट लेने की बजाय रन रोकने पर अधिक जोर रहेगा।

पहली बार कोटाम्बी में खेलने उतरेगी टीम इंडिया

इसके पहले यह मैदान भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला वनडे सीरीज की मेजबानी कर चुका है। न्यूजीलैंड के लिए पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत से मिली हार का खास महत्व नहीं है, क्योंकि यह श्रृंखला और दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों को परखने का अच्छा मौका है। टीम 2024-25 में भारत दौरे पर टेस्ट श्रृंखला में मिली 3-0 की ऐतिहासिक जीत की योजना को वनडे सीरीज में भी आजमाना चाहेगी। कई प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल टीम की अगुवाई कर रहे है। नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर ग्रोइन इंजरी के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि टॉम लाथम अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं। रचिन रवींद्र और तेज गेंदबाज जैकब डफी को आराम दिया गया है. पिंडली की चोट से वापसी कर रहे मैट हेनरी टी20 विश्व कप को ध्यान में रखकर टी20 सीरीज पर ध्यान दे रहे है। इस दौरान लंबे कद के हरफनमौला काइल जैमीसन और 23 वर्षीय लेग स्पिनर आदित्य अशोक के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी।

टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा।

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लर्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनॉक्स, माइकल रे. मैच दोपहर 1:30 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा।

मलेशिया ओपन से पीवी सिंधु बाहर, चीन की वांग ने 16-21, 15-21 से हराया

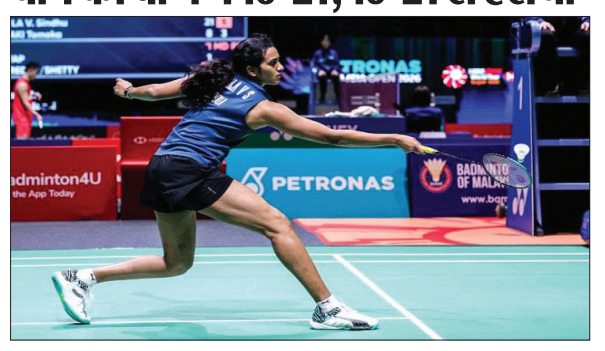

कुआलालम्पुर (एजेंसी)। क्वालालंपुर,(ईएमएस)। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन से बाहर हो गई हैं। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में उन्हें दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी चीन की वांग झियी ने 16-21, 15-21 से हरा दिया। सिंधु दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वांग झियी के खिलाफ दबाव नहीं बना सकीं। पैर की चोट से उबरने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही पीवी सिंधु ने दूसरे गेम में 11-6 की बढ़त भी गंवा दी। हार के साथ ही टूर्नामेंट में उनके सफर का निराशाजनक अंत हो गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीवी सिंधु ने वांग झियी को मुकाबले की शुरुआत में कड़ी टक्कर दी। उन्होंने जोरदार शॉट लगाए और अपने खास क्रॉस-कोर्ट स्मैश लगाकर 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन वांग के हल्के टच ने उन्हें लगातार अंक दिलाकर बराबरी पर ला दिया। पहले गेम में एक समय सिंधु 9-7 से आगे चल रही थीं, लेकिन चीनी खिलाड़ी वांग ने एक बार फिर वापसी की और इंटरवल पर सिंधु के नेट पर शॉट चूकने पर एक अंक की बढ़त बना ली। मैच फिर से शुरू होने के बाद स्कोर एक समय 13-13 से बराबर था। 15-14 पर, वांग ने लगातार आक्रामक शॉट्स से दबाव बढ़ाया। वह 18-14 पर पहुंच गईं, एक जबरदस्त रैली में एक अंक गंवाया, फिर चार गेम अंक हासिल किए और ओपनर खत्म किया क्योंकि सिंधु वाइड चली गईं।

दूसरे गेम में सिंधु दो गलतियों के बाद 1-3 पर फिसल गईं, लेकिन उन्होंने वापसी की और 6-3 से आगे निकलने के लिए जोरदार रैली बनाईं। वांग ने अंतर कम किया, फिर भी सिंधु ने बीच के समय में अपनी विरोधी खिलाड़ी को तेज एंगल से कोनों की ओर धकेलकर अपना दबदबा बनाया, जिससे ब्रेक तक 11-6 की बढ़त हो गई। वांग ने दोबारा गेम शुरू होने के बाद जोरदार वापसी की, तेज रैलियों में हिस्सा लिया, लेकिन सिंधु ने परफेक्ट नेट शॉट्स से जवाब दिया और 13-9 से आगे रहीं। वांग ने फिर वापसी की जब सिंधु के शॉट्स बाहर और नेट में चले गए और 13-13 से बराबरी कर ली। इसके बाद 16-13 की बढ़त के साथ वांग झियी ने मैच अपने नाम कर लिया।

डब्ल्यूपीएल 2026 की धमाकेदार शुरुआत, हार में भी इतिहास रच गईं हरमनप्रीत कौर

नई दिल्ली (एजेंसी)। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथों रोमांचक हार झेलनी पड़ी, लेकिन इस मुकाबले में एमआई की कप्तान ने एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल कर ली। नवी मुंबई में खेले गए इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने 20 रन बनाए और इसी के साथ वह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गईं। उन्होंने इस सूची में शेफाली वर्मा को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया।

हरमनप्रीत कौर के नाम अब डब्ल्यूपीएल में कुल 871 रन दर्ज हो गए हैं, जबकि शेफाली वर्मा 865 रनों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। इस उपलब्धि के साथ हरमनप्रीत ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मंच की खिलाड़ी हैं, भले ही उनकी टीम को इस मैच में जीत न मिल सकी। भारतीय बल्लेबाजों की इस सूची में स्मृति मंधाना तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। मंधाना अब तक डब्ल्यूपीएल में 664 रन ही बना पाई हैं और इस मुकाबले में भी उनका बल्ला खामोश रहा। वह 18 रन बनाकर आउट हो गईं।

अगर वुमेंस प्रीमियर लीग के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस की ही नैट साइवर-ब्रंट के नाम है। वह डब्ल्यूपीएल की एकमात्र बैटर हैं, जिन्होंने 1000 रन का आंकड़ा पार किया है। उनके नाम 1031 रन दर्ज हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर ऐलिस पैरी हैं, जिन्होंने 972 रन बनाए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मैग लेनिंग मौजूद हैं, जिनके नाम 952 रन हैं। हरमनप्रीत कौर चौथे और शेफाली वर्मा पांचवें स्थान पर काबिज हैं।

आरसीबी ने वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 में जीत के साथ की शुरुवात... लेकिन पूजा वस्त्राकर हुई चोटिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले मैच में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत के साथ शुरुआत की। टूर्नामेंट का ये पहला मैच मुंबई इंडियंस के साथ था। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अंतिम ओवर तक गया, जहां नादिन डी क्लेर्क ने दमदार खेल दिखाकर आरसीबी को जीत दिलाई। हालांकि, इस जीत के साथ ही आरसीबी को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल टीम की स्टार खिलाड़ी पूजा वस्त्राकर चोटिल हुई हैं। पूजा वस्त्राकर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है।

इसके बाद उन्हें पूरी तरह से रिकवर में होने में करीब दो सप्ताह का समय लगेगा। इस तरह पूजा अब लगभग आधे सीजन के लिए बाहर हो गई हैं। बता दें कि पूजा को आरसीबी ने इस बार के ऑक्शन में 85 लाख रुपए खर्च कर अपने स्क्वाड में शामिल किया है। पिछले सीजन में पूजा मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल थीं। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया। पूजा मुंबई के लिए तीन सीजन में खेली हैं।

पूजा वस्त्राकर के वूमेंस प्रीमियर लीग में अब तक कुल 16 मैचों में मैदान पर उतरी हैं। इसमें उन्होंने गेंदबाजी में 28.85 की औसत से 7 विकेट हासिल की हैं। पूजा सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग 14 रन देकर 2 विकेट लेने का है। इसके अलावा बल्लेबाजी में पूजा ने 16 मैचों में 116.66 की स्ट्राइक रेट से 126 रन बनाए। हालांकि, उनके ये आंकड़े कुछ खास प्रभावी नहीं हैं, लेकिन पूजा किसी टीम के लिए एक एक्स फैक्टर ऑलराउंडर मानी जाती हैं।

वहीं भारतीय टीम में पूजा को अब तक 5 टेस्ट, 33 वनडे और 72 टी20 में खेलने का मौका मिला है। टेस्ट क्रिकेट में पूजा ने टीम इंडिया के लिए 15 विकेट हासिल किए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में पूजा ने कुल 27 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि टी20 में उन्होंने 58 विकेट झटके हैं।

चीनी खिलाड़ी विजेझेंग ऑस्ट्रेलियाई ओपन नहीं खेलेंगी

बीजिंग । ओलंपिक पदक विजेता चीन की महिला टेनिस खिलाड़ी विजेझेंग किनवेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम वापस ले लिया है। किनवेन ने कहा है कि वह अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण टूर्नामेंट से हटी हैं। विजेझेंग ने कहा कि खेल से बाहर रहने का फैसला कठिन था पर उन्होंने ये फैसला मेडिकल टीम की सलाह के आधार पर लिया है। झेंग ने हालांकि कहा कि वह पहले से बेहतर हैं और उनकी रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है पर ग्रैंड स्लैम में प्रतिस्पर्धा करने का स्तर काफी ऊंचा होता है और उसमें अभी वह फिट नहीं बैठती हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी तक उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं पहुंची हूं जो होनी चाहिये। विजेझेंग ने कहा, मेलबर्न मेरी भाग्यशाली जगह है, जहां मैंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ मैच जीता और जहां मुझे अपना सबसे अच्छा अनुभव मिला। मेरा इस जगह से एक खास रिश्ता है, और मैं मेलबर्न में अपना नया सत्र शुरू करने के लिए उत्साहित थी। गौरतलब है कि विजेझेंग साल 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची। हालांकि तब उसे आर्यना सबालेंका के हाथों र का सामना करना पड़ा था।पिछले जुलाई में उनकी कोहनी की सर्जरी हुई थी जिसके बाद से ही वह खेल से दूर हैं।इस खिलाड़ी ने चाइना ओपन में वापसी की थी पर वहां उनकी चोट उबर गयी थी जिसके बाद से ही वह खेल से दूर थीं।

एशेज में जीत के पीछे बेहतर फील्डिंग की भी भूमिका रही : स्मिथ

सिडनी । ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज में टीम की जीत के लिए अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ ही टीम की फील्डिंग को भी श्रेय दिया। पैट कमिंस के फिट नहीं होने के कारण इस सीरीज में अधिकतर समय स्मिथ ने ही कप्तानी की थी। स्मिथ ने अंतिम टेस्ट मैच की सिडनी पिच की भी प्रशंसा की और कहा कि इसमें इसी के लिए कुछ न कुछ था। साथ ही कहा कि पिछले एक दशक में उन्होंने ये पिच सबसे अच्छी लगी। स्मिथ ने कहा, विकेट के बारे में मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में यहां खेलते हुए मैंने जितनी पिचें देखी हैं, उनमें से यह सबसे अच्छी है। मुझे लगता है कि इस पर सभी के लिए कुछ न कुछ था। नई गेंद थोड़ी काम कर रही थी। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते और खुद को संभालते, तो आप रन बना सकते थे। स्मिथ को यह भी लगा कि सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग शानदार थी और इससे भी परिणमा में अंतर आया। स्मिथ ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी फील्डिंग भी शानदार थी। मुझे लगा कि हमने जिस तरह से कैच पकड़े, वह इंग्लैंड से बेहतर थे। इससे भी परिणाम में अंतर आया। स्मिथ एशेज सीरीज में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इस शानदार बल्लेबाज ने चार मैचों और 8 पारियों में 57.20 की शानदार औसत से 286 रन बनाए।

गावस्कर ने निभाया वादा, महिला क्रिकेटर जेमिमा को गिफ्ट किया गिटार, गाना भी गाया

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक गिटार गिफ्ट किया है। गिटार खास है और निश्चित रूप से इस उपहार को जेमिमा ताउम्र याद रखेंगी। गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स को बैट के आकार का गिटार गिफ्ट किया है। जब जेमिमा ने गिफ्ट खोला, तो वह बहुत खुश दिख रही थीं, वह बैट के आकार के गिटार की कारीगरी की तारीफ कर रही थीं। दोनों ने एक साथ ये दोस्ती गाना गाया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गावस्कर द्वारा जेमिमा को बल्ले के आकार का गिटार दिए जाने का किस्सा महिला विश्व कप से जुड़ा हुआ है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार शतक लगाकर जेमिमा ने भारत को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। इस जीत के बाद गावस्कर ने उनसे कहा था कि अगर भारतीय टीम खिताब जीतती है, तो वह उनके साथ गाना गाएंगे। सुनील गावस्कर ने अपने उसी वादे को निभाया है। जेमिमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सुनील सर का इंतजार कर रही थीं कि वह अपनी बात मानें। अपनी प्रतिष्ठा के मुताबिक उन्होंने निराश नहीं किया। युवा क्रिकेटर ने सुनील गावस्कर से पूछा कि बल्ले के आकार का गिटार बजाने के लिए है या बल्लेबाजी के लिए। इस पर गावस्कर ने कहा कि वह दोनों कर सकती हैं। जेमिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा- सुनील सर ने अपना वादा निभाया और हमने अब तक के सबसे कूल बैट-आर के साथ जैमिंग की। यह एक स्पेशल था। बता दें सुनील गावस्कर और जेमिमा दोनों ही संगीत के शौकीन हैं। जेमिमा को अक्सर गाना गाते हुए भी देखा जाता है। हाल ही में क्रिकेटरों के सम्मान में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने गाना गाया था।

भारत-बांग्लादेश तनाव का असर क्रिकेट पर, भारतीय कंपनी एसजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों से तोड़ा करार

ढाका (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते कूटनीतिक और खेल संबंधी तनाव का असर अब सीधे क्रिकेट और उससे जुड़ी स्पॉन्सरशिप पर दिखाई देने लगा है। आईपीएल से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटरों को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत की जानी-मानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माता कंपनी 'एसजी' ने बांग्लादेश के शीर्ष क्रिकेटरों के साथ अपने स्पॉन्सरशिप अनुबंध को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है।

सूत्रों के मुताबिक, एसजी अब बांग्लादेश टीम के कप्तान लिटन दास, यासिर रब्बी और पूर्व कप्तान मोमिनुल हक के साथ अपना करार समाप्त करने जा रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इस फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खिलाड़ियों के एजेंट्स को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में एक क्रिकेटर के हवाले से कहा गया है कि आने वाले दिनों में यह फैसला औपचारिक रूप ले सकता है। इस घटनाक्रम को बांग्लादेश की खेल इंडस्ट्री के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एसजी के इस कदम के बाद अन्य अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियां भी बांग्लादेशी क्रिकेटरों को स्पॉन्सर करने से पीछे हट सकती हैं। प्लेयर स्पॉन्सरशिप से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कई ब्रांड जोखिम लेने से बचना चाहेंगे, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों की आय और बांग्लादेश क्रिकेट के व्यावसायिक ढांचे पर पड़ेगा।

दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत उस समय हुई, जब आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अनुरोध किया था कि भारत में होने वाले बांग्लादेश के मैचों को किसी अन्य देश, विशेषकर श्रीलंका, में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि आईसीसी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम को भारत आना होगा तथा खिलाड़ियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं घटनाओं के चलते भारत में मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध हुआ था। विरोध बढ़ने के बाद बीसीसीआई के निर्देश पर उन्हें रिलीज किया गया, जिससे दोनों क्रिकेट बोर्ड आमने-सामने आ गए।

श्रेयस अय्यर का डाग लव... पड़ जाता उनके क्रिकेट कैरियर पर भारी

नई दिल्ली । भारत के वनडे कप्तान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में वापसी को तैयार हैं। अय्यर रविवार, 11 जनवरी से शुरू हो रहे तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरने वाले है। पहले वनडे के लिए अय्यर वडोदरा पहुंचे गए, लेकिन यहां पर उनके साथ एक हादसा होते-होते बच गया। दरअसल अय्यर जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तब उन पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। हुआ यूं कि जब अय्यर एयरपोर्ट से निकलकर जब अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, तब रास्ते में कुछ फैंस उनके ऑटोग्राफ और सेल्फी की मांग करने लगे। तभी एक महिला फैन भी अपनी गोद में एक छोटे से कुत्ते को लेकर खड़ी थीं। यह देखकर अय्यर ने उस पमेरियन को देखकर पुचकारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि तभी उनसे झपट्टा मार दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि अय्यर ने फौरन अपने हाथ को पीछे खींचा और आगे बढ़ गए। इस तरह श्रेयस अय्यर डॉग बाइट से बाल-बाल बचे गए। बता दें कि अय्यर को पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। उन्हें ये चोट कैच लेने के प्रयास में लगी, जिसके कारण उनकी पसलियां फ्रैक्चर हो गया था। इंटरनल ब्लिडिंग होने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद वह लंबे समय के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पर रहे। इसकाारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे।

सेमीफाइनल में कोको गॉफ ने नंबर 2 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को हराया

सिडनी। यूनाइटेड कप के सेमीफाइनल में अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ गॉफ ने अमेरिका और पोलैंड के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया और अब मुकाबले का फैसला मिक्स्ड डबल्स से होगा।

गॉफ का स्वियातेक पर दबदबा बरकरार-फ्रेंच ओपन चैंपियन और विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज गॉफ की यह स्वियातेक पर लगातार चौथी जीत रही। इससे पहले पुरुष एकल मुकाबले में पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्कांच ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज़ को कड़े मुकाबले में 7-6 (1), 7-6 (2) से हराकर पोलैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई थी।

अब निर्णायक मुकाबले में गॉफ और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी पोलैंड की स्वियातेक और हर्कांच के खिलाफ मिक्स्ड डबल्स खेलेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को होने वाले फाइनल में स्विट्ज़रलैंड से भिड़ेगी।

स्विट्ज़रलैंड ने बेल्जियम को हराकर फाइनल में बनाई जगह-दूसरे सेमीफाइनल में स्विट्ज़रलैंड ने बेल्जियम को मिक्स्ड डबल्स में हराकर फाइनल का टिकट कटाया। निर्णायक मुकाबले में बेलिंडा बेनसिच और याकूब पॉल ने एलिस मर्टेंस और जिजू बर्ग्स को 6-3, 0-6, 10-5 से मात दी। बेनसिच इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक अपने सभी चार एकल मुकाबले और चार मिक्स्ड डबल्स मैच जीते हैं। कम अनुभव के बावजूद याकूब पॉल ने दबाव में शानदार डाउन-द-लाइन विनर्स लगाकर टीम को जीत दिलाई। बेनसिच ने कहा, 'वह बेहद साहसी हैं, यह अविश्वसनीय है। मैं उनसे खेलने को कहती हूं और वह सच में खेलने चले जाते हैं।

बेनसिच की दमदार वापसी, वावरिंका को मिली हार-इससे पहले बेनसिच ने एलिस मर्टेंस को 6-3, 4-6, 7-6 (0) से हराकर स्विट्ज़रलैंड को बढ़त दिलाई। वहीं, अपने करियर के अंतिम सत्र में खेल रहे स्टैन वावरिंका को जिजू बर्ग्स के हाथों 6-3, 6-7 (4), 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे सेट में आठवें गेम में ब्रेक निर्णायक साबित हुआ।

नीरज चोपड़ा ने लिया बड़ा फैसला, कोच जान जेलेज्नी से नाता तोड़ा

नई दिल्ली(एजेंसी)। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य के दिग्गज कोच जान जेलेज्नी के साथ अपनी साझेदारी एक ही सत्र के बाद समाप्त करने की घोषणा की है। चोपड़ा ने करार खत्म करने की कोई ठोस वजह नहीं बताई, लेकिन कहा कि यह सफर 'प्रगति, सम्मान और खेल के प्रति साझा लगाव' से भरा रहा।

जान जेलेज्नी, जिनके नाम भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, के मार्गदर्शन में नीरज चोपड़ा ने पिछले साल अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। चोपड़ा ने इस अनुभव को यादगार बताते हुए कहा कि बचपन के अपने आदर्श से प्रशिक्षण लेना किसी सपने के पूरे होने जैसा था। इससे उन्हें अभ्यास, तकनीक और खेल को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला।

नीरज ने कहा, 'जान जेलेज्नी के साथ काम करने से मुझे कई नए विचार मिले। वह तकनीक, लय और मूवमेंट को जिस तरह समझते हैं, वह अद्भुत है। हर सत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा।' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा गर्व उस दोस्ती पर है, जो उन्होंने अपने जीवनभर के आदर्श के साथ बनाई।

'जान सिर्फ सर्वकालिक महान भाला फेंक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं।' वहीं 59 वर्षीय जान जेलेज्नी ने भी इस साझेदारी को सकारात्मक बताते हुए कहा कि नीरज जैसे एथलीट के साथ काम करना उनके लिए शानदार अनुभव रहा। उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि हम साथ काम कर पाए और मैंने उन्हें पहली बार 90 मीटर पार करने में मदद की।'

जेलेज्नी ने यह भी कहा कि विश्व चैंपियनशिप को छोड़ दें तो नीरज ने अधिकांश प्रतियोगिताओं में कम से कम दूसरा स्थान हासिल किया, जो अपने आप में एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। हालांकि, टोक्यो से 12 दिन पहले लगी पीठ की चोट ने उनकी उम्मीदों को प्रभावित किया। आने वाले समय को लेकर जेलेज्नी ने नीरज की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें अभी भी अपार संभावनाएं हैं और दोनों के बीच मानवीय स्तर पर रिश्ता बेहद सकारात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में ट्रेनिंग कैंप या पारिवारिक छुट्टियों के दौरान भारत या यूरोप में फिर मिल सकते हैं।

नीरज चोपड़ा ने आगे की योजना पर कहा कि अब वह अपनी कोचिंग को लेकर खुद दिशा तय करेंगे। 'मैं 2026 को लेकर उत्साहित हूं। नवंबर की शुरुआत से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरा लक्ष्य हमेशा की तरह फिट रहना है और फिर से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना है।'

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका फोकस 2027 की विश्व चैंपियनशिप और उससे आगे 2028 ओलंपिक खेलों पर रहेगा। गौरतलब है कि पिछले साल दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर से अधिक का थ्रो करने के बाद नीरज विश्व चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर रहे थे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान में इमरान खान समर्थक की पुलिस की कार्रवाई में मौत

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के खिलाफ सेना और सरकार की दमनपूर्वक कार्रवाई जारी है। ताजा घटना में पंजाब पुलिस की कार्रवाई में एक पीटीआई समर्थक की मौत हो गई है। पीटीआई ने यह दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। उससे पहले पंजाब पुलिस की कार्रवाई में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक समर्थक की गुरुवार को मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पंजाब पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से इनकार किया और यह भी कहा कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक की मौत में उसकी कोई भूमिका नहीं है। खान की पार्टी ने दो साल पहले आम चुनावों में चुराए गए जनादेश के विरोध में 8 फरवरी को एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा पहले ही कर दी है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2022 में उनकी सरकार गिरने के बाद खान के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।

लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा हक

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका की नई विदेश नीति अब साफ तौर पर तीन मोर्चों पर आगे बढ़ती दिख रही है। ईरान में मानवाधिकार, लैटिन अमेरिका में अपराध और वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयानों से यह संकेत मिला है कि ट्रंप प्रशासन इन मुद्दों पर नरमी नहीं, बल्कि सीधी और कठोर नीति अपनाने के मूड में है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका उन सभी लोगों के साथ खड़ा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से गंभीर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। वेंस के मुताबिक, अमेरिका कैरीबियन और लैटिन अमेरिका में शांति को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टेल इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी अस्थिर करने वाली ताकत हैं। जब अवैध नशे के कारोबार से होने वाली कमाई पर रोक लगेगी, तब अपने आप हिंसा और अराजकता कमजोर पड़ेगी। अमेरिका इसी रणनीति के तहत सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वेनेजुएला को लेकर वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका वहां हालात को अस्थिर नहीं, बल्कि नियंत्रित और स्थिर देखना चाहता है। उन्होंने बताया कि नई सरकार पर लगातार नजर रखी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह अमेरिका के साथ तालमेल में काम करे। इसके लिए कई स्तरों पर नियमित बैठकें हो रही हैं। इन बयानों से साफ है कि ट्रंप प्रशासन विदेश नीति में दबाव, संवाद और शक्ति तीनों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का संदेश साफ है कि जहां अधिकारों का हनन होगा, वहां आवाज उठेगी और जहां अपराध और अव्यवस्था होगी, वहां सख्ती दिखाई जाएगी। आने वाले समय में इसका असर वैश्विक राजनीति पर साफ दिख सकता है।

वैश्विक दक्षिण को शांति-स्थिरता के लिए भारत के नेतृत्व की खास जरूरत

कोलंबो , एजेंसी। दक्षिण एशिया में लंबे वक्त तक शांति और स्थिरता के लिए भारतीय नेतृत्व की खास जरूरत है। यह बात गुरुवार को श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कही। राजपक्षे ने कहा कि हाल की बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच दक्षिण एशिया में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की बढ़ती और तत्काल जरूरत है और भारत इसमें केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। नमल राजपक्षे का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने राजनीतिक उथल-पुथल के दौर झेला है। कई बार इस दौरान हुई गड़बड़ियों को चरमपंथी तत्वों ने समर्थन और बढ़ावा दिया। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने, उग्रवाद व आतंकवाद का का मुकाबला करने, राजनीतिक हिंसा को रोकने और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। राजपक्षे ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया में लंबे वक्त तक शांति और सामंजस्य के लिए क्षेत्रीय एकता खासी अहम है और इस संदर्भ में भारत का नेतृत्व केंद्रीय है, क्योंकि भारतीय नेतृत्व में विकास और स्थिरता पर केंद्रित समान लक्ष्यों के साथ दक्षिण एशिया समग्र रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल में आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता की पुष्टि का एक आशाजनक मौका पेश करते हैं और यह क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूती देने में योगदान देगा।

ईरान में बढ़ रहा असंतोष, इंटरनेट-फोन सेवा निलंबित

खामेनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन

तेहरान , एजेंसी। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ सड़कों पर भारी बवाल मचा हुआ है। बीते दो हफ्तों से ईरान में महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई हैं। 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 45 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इधर, विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान ने तेहरान हवाई अड्डे को बंद कर दिया और हवाई सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर दिया है।

प्रदर्शनकारियों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि स्वीडन प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनता है और उनकी स्वतंत्रता के लिए साहसी लड़ाई का समर्थन करता है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ईरानी जनता एक बार फिर दमन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। हम उनकी आवाज सुनते हैं और स्वतंत्रता के लिए उनके साहसी संघर्ष का समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य की स्पष्ट मांगों को हिंसा और दमन से लंबे समय तक चुप नहीं कराया जा सकता।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी ईरान के प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की। बेल्जियम पीएम ने कहा, कई वर्षों के दमन और आर्थिक कठिनाइयों के बाद साहसी ईरानी स्वतंत्रता के लिए खड़े हो रहे हैं। वे हमारे पूर्ण समर्थन के पात्र हैं। हिंसा के माध्यम से उन्हें चुप कराना अस्वीकार्य है।

पूर्वी तेहरान में सरकारी इमारत में लगाई आग

राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में एक हिंसक घटना सामने आई। एक सरकारी इमारत में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इमारत को आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है, जबकि लोग सरकार विरोधी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।

निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने की राष्ट्रव्यापी इंटरनेटबंदी की निंदा

निर्वासित युवराज रजा पहलवी की ओर से प्रदर्शनों के आह्वान के बाद विरोध प्रदर्शन तेज होने पर ईरान ने गुरुवार रात को देशभर में इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय फोन सेवाएं बंद कर दीं। इंटरनेट कंपनियां क्लाउडफ्लेयर और नेटब्लॉक्स ने कहा कि यह व्यवधान सरकारी हस्तक्षेप के कारण हुआ, हालांकि ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इसकी पुष्टि नहीं की। वहीं रजा पहलवी ने ईरानी सरकार की निंदा की है। उन्होंने सभी यूरोपीय नेताओं से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का अनुसरण करते हुए ÷ईरान के लोगों का समर्थन करने÷ और ÷शासन को जवाबदेह ठहराने÷ का आह्वान किया।

ईरानी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद की वैश्विक समर्थन की अपील

प्रमुख ईरानी कार्यकर्ता और पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अलीनेजाद ने जारी विरोध प्रदर्शनों और फॉक्स न्यूज पर कहा कि ईरानी जनता का संदेश स्पष्ट है। जनता इस शासन को नहीं चाहती।

डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, एयरस्पेस बंद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (8 जनवरी) को धमकी दी कि अगर ईरानी अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो वाशिंगटन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और चेतावनी दी कि उन्हें ÷बहुत कठोर दंड÷ दिया जाएगा। इधर खामेनेई शासन ने एयरस्पेस बंद कर दिया है।

हिंसक प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 45 हो गई

बीते दो हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों में देर रात से अचानक तेजी देखने को मिली है। प्रदर्शनों के दौरान रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हैं। अब तक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में 45 लोगों की मौत हुई है जबकि 2200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। देशभर में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच ईरान ने तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे को बंद कर दिया है और देश भर में हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है। गुरुवार रात को देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अचानक तेजी देखने को मिली है। वहीं विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट और फोनकॉल सेवाएं बंद कर दी गई है।

ट्रंप ने मादुरो को माफ करने से किया इनकार, वेनेजुएला हमले पर यूक्रेन से तुलना को भी ठुकराया

वॉशिंगटन/काराकास, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को माफी देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि मादुरो ने ड्रग तस्करी गिरोह के लोगों को अमेरिका भेजा था, जिससे देश को गंभीर खतरा हुआ।

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा मादुरो को माफ नहीं किया जाएगा। यह बहुत लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन है और अमेरिका वेनेजुएला में लॉन्ग टर्म लक्ष्य लेकर आया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल कीमतें कम करने में करेगा और काराकास को वित्तीय सहायता भी देगा। अमेरिकी प्रशासन की ओर से देश की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व वाली सरकार के साथ काम सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि, रोड्रिग्ज ने हाल ही में ट्रंप को 'लालची' तक कह दिया।

रूस-यूक्रेन से तुलना खारिज

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की तुलना रूस के यूक्रेन हमले या चीन-ताइवान विवाद से करने पर ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मादुरो ने सीधे तौर पर अमेरिका के लिए खतरा पैदा किया और यह स्थिति चीन या रूस जैसी नहीं है।

अमेरिका का टारगेटेड ऑपरेशन

3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया। इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया है। ट्रंप ने यह कार्रवाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए देश में तस्करी और अन्य खतरों का हवाला दिया।

फिलीपींस के सेबू सिटी में लैंडफिल हादसा ; कचरे का ढेर गिरने से एक की मौत, 27 से अधिक लोग लापता

मनीला , एजेंसी। फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में स्थित सेबू सिटी में एक भयावह हादसा सामने आया है, जहां एक लैंडफिल साइट पर कचरे और मलबे का विशाल ढेर अचानक ढह गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, सात लोग घायल, जबकि कम से कम 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं, पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी।

यह हादसा बिनालिव गांव में स्थित एक वेस्ट सेग्रेगेशन फैसिलिटी में हुआ, जहां काम कर रहे मजदूर कचरे को अलग करने में जुटे थे। अचानक हुए इस कचरा धंसान ने वहां मौजूद कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार, राहत एवं बचाव दल ने अब तक आठ लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया है। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय एक महिला कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। शेष घायलों का इलाज जारी है।

तलाशी अभियान लगातार जारी : क्षेत्रीय पुलिस निदेशक ब्रिगेडियर जनरल रोडरिक माराना ने बताया कि तलाशी अभियान लगातार जारी है और लापता लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त वहां केवल कर्मचारी मौजूद थे या आसपास के निवासी भी प्रभावित हुए।

अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला : इस बीच, सेबू सिटी के मेयर नेस्टर आर्किवाल ने कहा कि राहत दल पूरी ताकत से खोज और बचाव कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 38 लोगों के लापता होने की सूचना भी सामने आई है। आंकड़ों में अंतर को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है। मेयर ने एक फेसबुक बयान में कहा सभी आपातकालीन टीमें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लापता लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी।

हादसे वाली जगह पर दर्जनों बचावकर्मी रातभर मलबा हटाने और लोगों को ढूंढने में जुटे रहे। बताया गया है कि जिस इमारत पर कचरे का ढेर गिरा, वह एक गोदाम था, जहां रीसायक्लिंग के लिए कचरा अलग किया जाता था।

अमेरिकी सांसद की खामेनेई को खुलेआम धमकी, बोले- ट्रंप तुम्हें मार डालेंगे, ईरान में तनाव के बीच मचा भूचाल

तेहरान/वाशिंगटन , एजेंसी। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद भारी तनाव है। इस बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को ट्रंप के नाम से जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा कि हम आपके साथ हैं। ट्रंप ओबामा नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने खामेनेई के लिए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आपको मार डालेंगे।

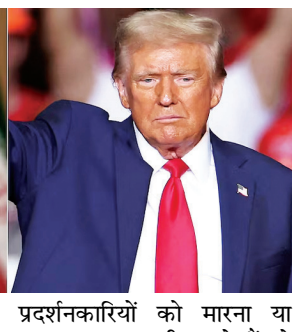

वेनेजुएला में घुसकर अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर की गई अमेरिकी कार्रवाई ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। इस बीच ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब अमेरिकी नेता ने ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दी है। अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता के लिंडसे ग्राहम ने ऐसा बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सनसनी फैला दी।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार देंगे, अमेरिकी सांसद की धमकी : अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही जारी तनाव अब और बढ़ गया है। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर (सांसद) लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मारना या घायल करना जारी रखते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घातक कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि अगर ईरानी नेतृत्व अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा जारी रखेगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मार देंगे।

खामेनेई को बताया धार्मिक नाजी: उन्होंने खामेनेई को एक धार्मिक नाजी बताते हुए कहा कि वो एक धार्मिक नाजी है, जो अपने ही लोगों को मारता है और दुनिया को आतंकित करता है। ग्राहम ने यह टिप्पणी फॉक्स न्यूज पर अपनी मौजूदगी के दौरान कीं। जिसमें उन्होंने ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का जिक्र किया। द शॉन हैनिटी शो के दौरान ईरानी नागरिकों को संबोधित करते हुए ग्राहम ने कहा कि हम आज रात आपके साथ खड़े हैं।

ईरान के लोगों से कहा- मदद आ रही है : मंगलवार (7 जनवरी) दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने लोगों को बेहतर जीवन की मांग पर मारते रहे, तो डोनाल्ड जे. ट्रंप तुम्हें मार देंगे। अयातुल्ला और उसके गुंडों, अगर तुम ट्रंप की चेतावनी को चुनौती देते रहे, तो तुम सुबह मरे हुए पाए जाओगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करते हुए यह भी कहा कि मदद आ रही है।

हमले की आशंका के बीच ट्रंप को डेनमार्क ने दी चेतावनी

कोपेनहेगन , एजेंसी। डेनमार्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर एक कड़ी चेतावनी दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी भी शक्ति द्वारा ग्रीनलैंड पर हमला किया जाता है तो उसके सैनिक पहले गोली चलाएंगे और बाद में सवाल पूछेंगे यानी बिना किसी अनुमति या आदेश का इंतजार किए तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह आदेश 1952 के ठंडे युद्ध के नियमों के तहत है, जो किसी भी विदेशी आक्रमण के जवाब में तुरंत प्रतिरोध की आवश्यकता को कहता है। डेनिश रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह 1952 का आदेश अब भी लागू है और इसका उद्देश्य किसी भी संभावित आक्रमण के मामले में तुरंत जवाब देना है। मंत्रालय ने कहा कि नियम के तहत सैनिकों को ऊपर के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि हमले की स्थिति में तुरंत युद्ध में उतरना होगा।

अमेरिका ग्रीनलैंड पर करना चाहता है नियंत्रण : ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्वायत्त क्षेत्र है, जो डेनमार्क के शासन में आता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है और यह बात सामने आई है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य शक्ति का उपयोग भी शामिल हो सकता है।

नाटो सदस्य का ग्रीनलैंड को समर्थन : इस चेतावनी के बीच यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ी है। फ्रांस, जर्मनी और अन्य नाटो सदस्य ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका को सामूहिक रूप से स्थिति को शांत करने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वह बातचीत और कूटनीतिक उपायों के लिए तैयार है, पर ट्रंप के आक्रामक रुख ने यूरोपीय नेताओं में बेचैनी पैदा कर दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और किसी भी प्रकार के आजमाए गए कब्जे को खंडित कर दिया जाएगा।

ट्रंप को डेनमार्क ने दी चेतावनी : डेनमार्क की पीएम ने साफ शब्दों में ट्रंप से कहा, डेनमार्क साम्राज्य और ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा हैं। इसकी वजह से यह गठबंधन की सुरक्षा गारंटी के तहत आता है। डेनमार्क और अमेरिका के बीच पहले से ही एक रक्षा समझौता है, जो अमेरिका को ग्रीनलैंड तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा, इसी आधार पर मैं अमेरिका से आग्रह करती हूं कि वह ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ सहयोगी और एक ऐसे देश और लोगों के खिलाफ धमकियां देना बंद करे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बिकने वाले नहीं हैं।

शांति का संकेत या दबाव में वेनेजुएला की सरकार, जानें राजनीतिक कैदियों की रिहाई के क्या मायने

काराकास , एजेंसी। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के बाद से वहां के हालात ठीक नहीं है। फिलहाल राष्ट्रपति का कार्यभार डेल्सी रोड्रिगेज संभाल रही हैं। वो वहां की अंतरिम राष्ट्रपति चुनी गई हैं। यहां के सियासी हालात एक बार फिर चर्चा में हैं। सरकार ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का एलान किया है। इस फैसले को सरकार शांति बनाए रखने की एकतरफा पहल बता रही है, लेकिन इसे विपक्ष और अमेरिका के दबाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

वेनेजुएला की संसद के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज ने गुरुवार को कहा कि सरकार महत्वपूर्ण संख्या में कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रही है। इसमें वेनेजुएला के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी कैदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम देश में शांति, स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उनके मुताबिक, कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया इसी समय से शुरू हो चुकी है।

नई सरकार का रुख और संकेत : यह घोषणा नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार के पहले बड़े राजनीतिक फैसलों में गिनी जा रही है। माना जा रहा है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी की दिशा में शुरुआती संकेत हो सकता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह किसी दबाव में नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया एकतरफा कदम है।

मादुरो दौर की गिरफ्तारियां : मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, वेनेजुएला में इस समय 800 से 900 के बीच राजनीतिक कैदी हैं। इनमें से ज्यादातर गिरफ्तारियां पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के शासनकाल में हुई थीं। हाल ही में मादुरो को अमेरिकी बलों द्वारा पकड़े जाने के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसी पृष्ठभूमि में कैदियों की रिहाई को अहम माना जा रहा है।

अमेरिका, विपक्ष और परिवारों का दबाव

वेनेजुएला में बीते वर्षों में कई अमेरिकी नागरिकों को भी जेल में रखा गया था। जनवरी 2025 में छह अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया था, जब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने काराकास में बातचीत की थी। लंबे समय से कैदियों के परिवार और विपक्षी समूह रिहाई की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर यूएस सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि मादुरो पर ट्रंप की कार्रवाई के बाद से यहां के हालात बदल चुके हैं।

नहीं चलेगी मनमानी ! 66 संगठनों से अमेरिका की दूरी पर यूएन ने कहा- जिम्मेदारी से नहीं बच सकता यूएस

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े और चौंकाने वाले फैसले ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 31 निकायों समेत कुल 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और पहलों से खुद को अलग करने का ऐलान किया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि अमेरिका पर यूएन एजेंसियों को फंड देने की कानूनी जिम्मेदारी बनी हुई है।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्रंप के फैसले पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट और शांति मिशनों के लिए सदस्य देशों द्वारा दी जाने वाली राशि कोई विकल्प नहीं, बल्कि यूएन चार्टर के तहत कानूनी दायित्व है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने स्पष्ट किया कि अमेरिका सहित सभी सदस्य देशों पर यह जिम्मेदारी लागू होती है।

किस तरह का फैसला लिया गया

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों से अमेरिकी समर्थन निलंबित कर दिया है। इनमें 35 गैर-यूएन संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकाय शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रही हैं और वोक एजेंडे को बढ़ावा देती हैं। व्हाइट हाउस की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी गई, जबकि यूएन को इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई।

जलवायु संस्थानों पर असर

इस फैसले का सबसे गहरा असर पर्यावरण और जलवायु से जुड़े वैश्विक संगठनों पर पड़ा है। अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से भी दूरी बना ली है। जलवायु संधियों से हटने का यह कदम अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा, क्योंकि ट्रंप पहले भी पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जिन एजेंसियों से अमेरिका हट रहा है, वे अपना काम जारी रखेंगी। यूएनएफसीसीसी के प्रमुख साइमन स्टील ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस फैसले से उसकी अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीवन स्तर को नुकसान होगा, क्योंकि जलवायु संकट तेजी से गंभीर होता जा रहा है। हालांकि यूएन ने यह भी कहा है कि भविष्य में अमेरिका के लिए दोबारा लौटने के दरवाजे खुले रहेंगे।

ट्रंप के फैसले पर एक नजर

अमेरिका ने वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और मंचों से हटने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार, अमेरिका उन संस्थाओं से दूरी बना रहा है, जो उसके मुताबिक राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं।

इस फैसले में 35 गैर-यूएन संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकाय शामिल हैं। इनमें पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा, श्रम, प्रवासन और सामाजिक विकास से जुड़े कई अहम वैश्विक मंच हैं। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड, यूएन वाटर, यूएन एनर्जी और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जैसे संगठनों पर भी इसका असर पड़ेगा। आदेश में सभी अमेरिकी विभागों को तत्काल प्रभाव से फंडिंग और भागीदारी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को से अमेरिका को बाहर कर चुका है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद

सांबा (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद की गई है। अधिकारियों के अनुसार, खेप में दो पिस्तौल, तीन मैगजीन, 16 कारतूस और एक ग्रेनेड शामिल हैं। यह बरामदगी तब हुई है जब गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी की गई है। सेना अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने पलोरा गांव में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान एक नाले के किनारे पीले टेप में लिपटा एक संदिग्ध पैकेट मिला। बम निरोधक दस्ते की सहायता से जब पैकेट को सुरक्षित तरीके से खोला गया, उसमें से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ। इसी बीच, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग सेक्टर में एक दुखद घटना सामने आई। नियंत्रण रेखा के पास ढलान से फिसलकर गिरने से सेना के दो नागरिक कुलियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लियाकत अहमद दीदार और इशाक अहमद खटाना के रूप में हुई है, जो बारामूला के चंदूसा इलाके के निवासी थे। दोनों गुरुवार दोपहर एक अग्रिम क्षेत्र से फिसलकर नाले में गिर गए थे। घटना के बाद सेना ने व्यापक बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद उनके शव बरामद किए गए।

लुधियाना के लग्जरी कार शोरूम के बाहर हुई फायरिंग, मर्सिडीज और रेंज रोवर की गाड़ियों के शीशे टूटे

लुधियाना (एजेंसी)। पंजाब के लुधियाना जिले में शनिवार को दिनदहाड़े एक गंभीर घटना को अंजाम दिया गया। मुल्लापुर नजदीक बद्दोवाल इलाके में स्थित लग्जरी कार शोरूम रॉयल लीमोज पर बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह हमला सुबह करीब साढ़े दस बजे हुआ, जब शोरूम के कर्मचारी ऑफिस में मौजूद थे। फायरिंग में मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियों के शीशे टूट गए और उन्हें खासा नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी अनुसार फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने शोरूम के बाहर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम की पर्चियां भी फेंकीं। इससे यह प्रतीत हुआ, कि यह घटना गैंगवार या रंगदारी से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में इस मामले को रंगदारी से जुड़ा माना है।

फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश बाइक से उतरकर शोरूम और वहां खड़ी गाड़ियों पर गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में फायरिंग करने के बाद वह पैदल ही भागता हुआ दिखाई देता है। पुलिस का मानना है कि दूसरा बदमाश बाइक लेकर वहां खड़ा था। फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

मुफ्ती नूर अहमद नूर भारत में अफगानिस्तान दूतावास के सीडीए नियुक्त

नई दिल्ली (एजेंसी)। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य मुफ्ती नूर अहमद नूर को भारत में अफगानिस्तान दूतावास का चार्ज डीअफेयर्स (सीडीए) नियुक्त किया गया है। नूर अहमद इसके पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में फर्स्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति से अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में नई गर्मजोशी का संकेत मिलता है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आई। इस दौरान समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके तहत तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों को अफगान दूतावास में स्वीकार किया गया था। भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भारत एक अहम सहयोगी देश बनकर उभरा है। भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा आपूर्ति, सहायता और अन्य सहयोग जारी रखा है। वहीं, मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों में भी तालिबान द्वारा नियुक्त राजदूत कार्य कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण डेलीगेशन ने दौरे किए हैं। इनमें व्यापार, ऊर्जा, और चाबहार पोर्ट के विकास को लेकर सहमति बनी है। भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान में निवेश को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करना है।

दर्दनाक हादसा! सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी स्कूटी, एक ही परिवार के 3 की मौत

जमशेदपुर(एजेंसी)। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित हाइवा से टकराने के कारण तीन युवाओं की अकाल मृत्यु हो गई। यह दर्दनाक हादसा मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुरदा में बीती शाम सवा सात बजे यूनियन बैंक के समीप हुआ। इस दुर्घटना में दो सगे भाइयों और उनके एक भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार, घाटशिला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी राहुल कर्मकार अपने दो सगे भाइयों, रोहित कर्मकार और समीर कर्मकार, तथा अपने भांजे राज गोप के साथ एक ही स्कूटी पर सवार होकर दिन में अपने ससुराल गया था। रात को वापसी के दौरान, जब वे सुरदा यूनियन बैंक के पास पहुंचे, तो उनकी स्कूटी सड़क किनारे खराब खड़े एक हाइवा के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 21 वर्षीय रोहित कर्मकार, 18 वर्षीय समीर कर्मकार और 17 वर्षीय राज गोप ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। 26 वर्षीय राहुल कर्मकार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही घाटशिला और मुसाबनी पुलिस बल मौके पर और अस्पताल पहुंचा। इस घटना के बाद जगन्नाथपुर और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ अस्पताल परिसर में जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रोहित और घायल राहुल दोनों शादीशुदा थे और घाटशिला क्षेत्र में पुट्टी करने का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता

किशोर प्रेम संबंधों को अपराध श्रेणी से अलग रखने रोमियो-जूलियट क्लॉज पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए पॉक्सो (पीओसीएसओ) कानून के कथित दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि वह इस कानून में 'रोमियो-जूलियट' क्लॉज जोड़ने पर विचार करे, ताकि 16-17 वर्ष की किशोरियों और 18-19 वर्ष के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध की श्रेणी में आने से रोका जा सके। यह कदम खासकर उन मामलों में उठाया जाएगा, जहां किशोरों के रिश्ते पूरी तरह से आपसी सहमति पर आधारित होते हैं, लेकिन कानून की सख्ती के कारण उन्हें अपराधी करार दिया जाता है।

कानूनी दृष्टिकोण से, वर्तमान समय में 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति को मान्यता नहीं मिलती, जिससे ऐसे रिश्तों में लड़कों के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पॉक्सो जैसे सख्त कानून का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जाए, ताकि संभावित संशोधनों को लागू किया जा सके। पीठ का यह कहना था कि ऐसे मामले में विशेष ध्यान रखा जाए, जिसमें कोई व्यक्ति केवल बदले की भावना से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से पॉक्सो कानून का दुरुपयोग कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा बनाए रखना है, जबकि साथ ही किशोरों को बिना कारण अपराधी बनने से बचाना भी है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन कुछ टिप्पणियों को गलत ठहराया। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पॉक्सो मामलों में जमानत सुनवाई के दौरान मेडिकल एज टेस्ट कराने की बात नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित की उम्र का निर्धारण ट्रायल कोर्ट का कार्य है, न कि बेल कोर्ट का। बेल कोर्ट केवल प्रस्तुत दस्तावेजों को देख सकता है, लेकिन उसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकता।

अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले सीएम धामी, फिर केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि अंकिता के माता-पिता से मुलाकात के दौरान उनके दुख और कठिनाइयों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवार को न्याय सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सीएमओ के अनुसार, धामी ने देहरादून में अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी से मुलाकात की, जहां शोक संतप्त परिवार ने अपनी भावनाएं और विचार साझा किए। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक लगाई है। कोर्ट ने कई प्रतिवादियों, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल हैं, पर यह रोक लगाई और प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला माना। यह विवाद उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा है, जिसका शव सितंबर 2022 में एक नहर से बरामद हुआ था। मुख्यमंत्री धामी का यह कदम पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। इसके साथ ही, न्यायालय का निर्णय सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और मानहानि को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी उभर रही हैं, जैसे कि कोयला तस्करी और टीएमसी चुनावी डेटा विवाद में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा ईडी की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक करार देना।

राजनीति में सिद्धांतों के साथ सत्ता का होना भी अनिवार्य: सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (एजेंसी)। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी प्रचार के दौरान गठबंधन की मजबूरियों, पार्टी की भावी नीतियों और मुंबई के विकास के रोडमैप पर खुलकर अपनी बात रखी। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राजनीति में सिद्धांतों के साथ-साथ सत्ता का होना भी अनिवार्य है ताकि जनहित की नीतियों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा जा सके। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने एक बड़ा वैचारिक तर्क पेश किया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह अड़ी रही, तो पार्टी को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। महाभारत के युद्ध का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा और नीतियों को लागू करने के लिए उस काल में भी कई समझौते किए गए थे। उन्होंने अजीत पवार को एक लचीला नेता बताते हुए कहा कि यह गठबंधन बहुत सोच-समझकर किया गया है। फडणवीस ने साफ किया कि भले ही स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ रही हों, लेकिन 2029 के विधानसभा चुनाव और भविष्य के लिए महायुति गठबंधन पूरी तरह एकजुट और मजबूत है।

मुफ्त उपहारों की बढ़ती संस्कृति और राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे लोकलुभावन वादों पर भी उपमुख्यमंत्री ने बेबाकी से अपनी राय रखी। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे द्वारा घरेलू सहायिकाओं को हर महीने 1,500 देने के वादे और खुद भाजपा द्वारा नवी मुंबई में 20 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स न बढ़ाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह वर्तमान राजनीति का एक ऐसा चलन है जिससे कोई भी दल अछूता नहीं रह सकता। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले पांच वर्षों में यह स्थिति बदल सकती है। मुंबई के बुनियादी ढांचे को लेकर फडणवीस ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने मुंबईकरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बांद्रा सी-लिंक से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक एक विशेष टनल (सुरंग) बनाने का वादा किया। इस योजना के तहत एक टनल कुर्ला की ओर और दूसरी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाएगी, जो आगे चलकर कोस्टल रोड से जुड़ जाएगी। इसके अलावा, मेट्रो लाइनों का विस्तार और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उन्होंने शहर में अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात भी कही। फडणवीस ने स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर नेताओं के आपसी मनमुटाव के कारण कुछ जगहों पर गठबंधन न हो पाना एक चूक थी, जिसे भविष्य में सुधारा जाएगा।

आई-पैक मामले में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल की

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शनिवार को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट एप्लीकेशन दाखिल की है। यह कदम तब उठाया गया है, जब आई-पैक से जुड़े मामले में ईडी के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की संभावनाएं थीं। कैविएट दाखिल कर बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत से स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि यदि मामले में कोई भी याचिका या अपील दायर होती है, तब राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न करे। ममता सरकार के कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत किसी भी एकतरफा आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका दे। दरअसल, ममता सरकार को आशंका थी कि ईडी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। यह देखकर ममता सरकार की ओर से कैविएट एप्लीकेशन दाखिल की गई है। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय भी पूरे मामले में अपनी कानूनी रणनीति पर मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि ईडी भी कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना भी शामिल है। हालांकि, अंतिम फैसला लेने से पहले ईडी सभी पहलुओं और संभावित कानूनी रास्तों का आकलन कर रही है।

इसके पहले, ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि उसकी जांच में जानबूझकर रुकावट पैदा की गई ताकि काम प्रभावित हो जाए। ईडी की ओर से दायर याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। साथ ही, एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर संबंध में केस दर्ज करने की भी अनुमति मांगी। इस दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई अहम दस्तावेज और जानकारियां अपने साथ ले गईं।

एनसीआर में प्रदूषण और ठंड का दोहरा प्रकोप जारी, राहत नहीं - दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हुई हल्की बारिश के बावजूद वायु प्रदूषण में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिल्ली के नरेला, नेहरू नगर, पंजाबी बाग, पूसा, आरके पुरम और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। खासतौर पर आनंद विहार में एक्यूआई 425 तक पहुंच गया, जबकि नेहरू नगर में यह 428 और चांदनी चौक में 408 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अशोक विहार, बवाना, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज और डीटीयू इलाके में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी रही। नोएडा में सेक्टर-125 का एक्यूआई 358, सेक्टर-1 का 397 और सेक्टर-62 का 364 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में वसुंधरा का एक्यूआई 432 तक पहुंच गया, जो गंभीर स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा इंदिरापुरम, लोनी और संजय नगर में भी प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च रहा। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री के आसपास रहा। नमी अधिक होने से कोहरा और प्रदूषण का असर और बढ़ गया। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है और ठंड व कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम और प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश कम होने और हवा की गति धीमी होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे रहे। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी रोग वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। बाहर निकलते समय मास्क पहनना और घर के अंदर शुद्ध हवा बनाए रखना जरूरी है।

ओवैसी ने कहा, एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी... बीजेपी की खुली चुनौती

पहले पसमांदा मुस्लिम या हिजाब वाली महिला को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाए

सोलापुर (एजेंसी)। भारतीय संविधान की खूबसूरती की तारीफ कर एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा में ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता नहीं है, जो अन्य धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन भारत में बाबा साहब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ आप जो नफरत फैला रहे हैं, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नफरत फैलाने वालों का अंत जरूर होगा। जब प्यार आम हो जाएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि लोगों के दिमाग में कैसे जहर घोला गया था।

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देकर उन्हें चुनौती दी कि वे किसी पसमांदा मुस्लिम या हिजाब पहनने वाली महिला को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने पोस्ट कर कहा, 'हिजाबवाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, मियां ओवैसी कहते हैं। मियां ओवैसी....संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि पहले किसी पसमांदा या हिजाबवाली को एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाकर दिखाएं।'

इसके पहले ओवैसी ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों को मजबूत करने के लिए आलोचना की थी, इस कारण विद्वान उमर खालिद और शरजील इमाम सहित विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो विचाराधीन आरोपियों को जमानत नहीं दी और जमानत न देने के कारणों का स्पष्टीकरण भी दिया।

अयोध्या के बाद अब पूरे देश में मंदिरों के बाहर मांसाहारी दुकानों पर प्रतिबंध लगे : चंदौलिया

-निजी कंपनी को बचाने हर हद पार कर रही ममता सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने अयोध्या में राम मंदिर के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगने के बाद सभी मंदिरों के पास मांस और शराब की दुकानों पर बैन लगाने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के पास मांसाहारी भोजन की दुकानें होना सही नहीं है और यह फैसला पूरे देश में लागू करना चाहिए। इतना ही नहीं सांसद चंदौलिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कोलकाता में ईडी अधिकारियों की छापेमारी के दौरान उत्पन्न विवाद का जिक्र कर कहा कि राज्य में आतंक और गुंडागर्दी का माहौल है और ममता सरकार निजी कंपनी की सुरक्षा के लिए सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कभी साथ ही हैं, कभी लड़ाती हैं, यह नूराकुश्ती राज्य की जनता देख रही है।

सांसद चंदौलिया ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में बदलाव के दावों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया, जिससे वह अपने सिस्टम में बदलाव के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई भी आतंकवादी घटना होती है, तब भारतीय सेना कड़ा जवाब देगी। बात दें कि सांसद चंदौलिया का यह बयान अयोध्या के मंदिरों के आसपास सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मान बनाए रखने, देश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

महिलाओं के लिए बेहतर शहरों में, बंगलुरू सबसे आगे, टॉप-10 में गुरुग्राम ने लगाई लंबी छलांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, काम के समान अवसर और सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर की गई एक विस्तृत स्टडी के बाद वूमेन-फ्रेंडली शहरों की नई सूची जारी कर दी गई है। देश के 125 शहरों के गहन आकलन के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट में कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू ने एक बार फिर बाजी मारी है। रिपोर्ट के अनुसार, बंगलुरू महिलाओं के रहने, काम करने और करियर में आगे बढ़ने के लिहाज से देश का सबसे अनुकूल शहर बनकर उभरा है।

इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए सिटी इन्क्लूजन स्कोर (सीआईएस) को आधार बनाया गया है, जिसमें सामाजिक समावेश (सोशल इन्क्लूजन) और औद्योगिक समावेश (इंडस्ट्रियल इन्क्लूजन) दोनों को मापा गया। बंगलुरू ने 53.2 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। आईटी और स्टार्टअप हब होने के नाते यहाँ बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, रोजगार के प्रचुर अवसर और डिजिटल सशक्तीकरण जैसी खूबियां महिलाओं के पक्ष में रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ महिलाएं सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अनुभव करती हैं। सूची में दूसरा स्थान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को मिला है, जिसने 49.8 का स्कोर हासिल किया। चेन्नई ने विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सुरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र का पुणे शहर तीसरे स्थान पर रहा, जहाँ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और जीवन स्तर में सुधार देखा गया। इसके बाद चौथे स्थान पर हैदराबाद और पांचवें स्थान पर सपनों की नगरी मुंबई रही। मुंबई को 44.4 की रेटिंग मिली है, हालांकि यह स्कोर के मामले में बंगलुरू से काफी पीछे रह गई है।

इस बार की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला सुधार हरियाणा के गुरुग्राम में देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से टॉप-10 में जगह बनाने वाला गुरुग्राम इकलौता शहर रहा। पिछली रैंकिंग में नौवें स्थान पर रहने वाला यह शहर तीन पायदान की छलांग लगाकर छठे स्थान पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली और नोएडा जैसे प्रमुख शहर इस बार शीर्ष 10 की सूची में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। रैंकिंग में सातवें स्थान पर कोलकाता रहा, जबकि गुजरात के अहमदाबाद को आठवां स्थान मिला। अहमदाबाद में महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) की सुविधाओं को सराहा गया। कोयंबटूर ने दसवें स्थान पर रहकर सबको प्रभावित किया, जहाँ स्ट्रीट लाइट ऑडिट और देर रात सफर करने वाली महिलाओं के लिए कम जोखिम भरे माहौल की प्रशंसा की गई। 2022 से अब तक के आंकड़ों पर आधारित यह 2025 की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत के शहरी ढांचे में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और समावेशिता धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे महिलाएं अब सामाजिक और पेशेवर दोनों मोर्चों पर खुद को अधिक सशक्त महसूस कर रही हैं।